



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1995/अश्विन 1, 1917

No. 38]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1995/ASVINA 1, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य
क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक
नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1995

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 8th September, 1995

मा. का. नि. 426.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधि-
नियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 208 की उप-
धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह
निर्देश देती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी
दशा में ब्याज की दर प्रतिवर्ष ब्राह्म प्रतिशत में अधिक
नहीं होगी।

G.S.R. 426.—In exercise of the powers conferred by
sub-section (6) of Section 208 of the Companies Act, 1956
(1 of 1956), the Central Government hereby directs that rate
of interest shall in no case exceed twelve per cent per annum
for the purposes of said section.

[नं. 28/1/94-सी एल.-3]
धर्मपाल, अव्वर सचिव

[No. 28/1/94-CL.III]
DHARAM PAL, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1995

मा. का. नि. 427.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1971 को उन बातों के विषय अधिकांत करने हुए, जिन्हें ऐसे
अधिकरण में पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर
भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताने हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति:—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (लेखा)	4* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित अनुसचिवीय	3000-100- 3500-125- 4500/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य शर्तें

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परीक्षा की अवधि यदि कोई हो लिए विहित आयु और शैक्षिक शर्तें
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>		
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा</p>		
11	12	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐसा संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा)/लेखा परीक्षा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा)/लेखा परीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : 1 इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के ऐसे नियमित पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है प्रोन्नत के लिए पात्र बने रहेंगे।</p> <p>टिप्पण:—2. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी शर्ह/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित शर्ह/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 2200—4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 2375—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है, या (iv) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और</p>	

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री या समतुल्य
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय या निकाय या वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

पांचवक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मन्त्रालय—सदस्य

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. आई-45027/61/93/कार्मिक-2]

एन. जे. थामस, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th September, 1995

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Reserve Police Force Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Central Reserve Police Force, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in

consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Accounts)	4* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Non-Ministrial	Rs. 3000 -100-3500-125-4500/-.	Selection	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
12	13	14
<p>Promotion:</p> <p>Joint Assistant Director (Accounts)/Audit Officer with 7 years' regular service in the grade failing which 8 years' combined regular service in the grades of Joint Assistant Director (Accounts)/ Audit Officer and Section Officer/Administrative Officer</p> <p>Note: 1. The existing regular incumbents of the post of Joint Assistant Director (Accounts)/Audit Officer on the date of notification of these rules shall continue to be eligible for promotion with 5 years regular service in the grade.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</p> <p>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission--Chairman.</p> <p>2. Director General, Central Reserve Police Force--Member</p> <p>3. Joint Secretary Police, Ministry of Home Affairs- Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion</p>

Note: 2. Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period.

Transfer on deputation:

Officers under the Central/State Governments:—

A. (i) Holding analogous posts on regular basis;

OR

(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent;

OR

(iii) with 7 years' regular service in posts in the scale Rs. 2375-3500 or equivalent;

OR

(iv) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent;

AND

B. Possessing the following qualifications and experience:—

(i) Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) Five years' experience of administration, accounts and Establishment work in a supervisory capacity in a Government office or Body or Commercial Organisation.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application).

[File No. I-45027/61/93-Pers. II]

N. J. THOMAS, Desk Officer

गुप्तपत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1995

सा.का.नि. 428.—भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (1) में पृष्ठ 1460 से 1470 पर प्रकाशित भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 1 जुलाई 1995

की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309 में निम्नलिखित सुधार किया जाय :

1. अनुसूची के स्तम्भ 7 में दोनों पदों अर्थात् सहायक निवेशक (विधि) और सहायक निवेशक (प्रवक्ता) के लिए "नहीं" शब्द के स्थान पर "लागू नहीं" शब्द अन्तः स्थापित किए जायें।

2. अनुसूची के स्तम्भ 12 में दोनों पदों अर्थात् सहायक निदेशक (विधि) और सहायक निदेशक (प्रवक्ता) के लिए अंतिम पैराग्राफ में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक सविदा सहित)/स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयु सीमा" के स्थान पर "स्थानान्तरण" शब्द को हटा कर "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक सविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा" वाक्य अन्तर्स्थापित किया जाये।

[फा.सं. 5/2/95-एन.ई.-II]

श्रीमती एल. तोछोंग, निदेशक
(एन ई सी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th September, 1995

G.S.R. 428.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 309 dated

the 1st July, 1995, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) at pages 1460 to 1470, the following may be corrected :—

1. In Column 7 of the Schedule for both the posts i.e. Assistant Director (Law) and Assistant Director (Lecturer), the words 'Not applicable' may be inserted in place of word 'No'.
2. In Column 12 of the Schedule for both the posts i.e. Assistant Director (Law) and Assistant Director (Lecturer) in the last paragraph, the sentence 'Maximum age limit for transfer on deputation (including short-term contract)' may be inserted in place of 'Maximum age limit for transfer on deputation (including short-term contract)/transfer by deleting the words 'transfer'.

[F. No. 5/2/95-NE.II]

SMT. L. TOCHHONG, Director (NEC)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1995

सा. का. नि. 429.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यिकी वैज्ञानिक और सविस् इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यिकी वैज्ञानिक और सविस् इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यिकी वैज्ञानिक और सविस् इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक और ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार) के पद से संबंधित क्रम सं. 1 और उनसे संबंधित प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा
						केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक	15* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अनुसूचितीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या	हां

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

अननुसन्धिवीय

आदेशों के अनुसार सरकारी संवकों के लिए पांच वर्ष तक शिक्षण की जा सकती है।)

टिप्पणः—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के नद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिचीना की अवधि, यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक :

आयु : नहीं

सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रमाणित विज्ञान या समुद्री जीवविज्ञान या मात्स्यिकी प्रबंध या समुद्री विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई से मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य,

- (ii) समुद्री मात्स्यिकी जिसके अंतर्गत परिभ्रमण योजना और समुद्री यात्राओं में भाग लेना भी है, के सर्वेक्षण या अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणः—1. अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(8)

टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्ह-
ताएं) संघ लोक सेवा आयोग
के विवेकानुसार अनुसूचित
जातियों और अनुसूचित जन-
जातियों के अभ्यर्थियों की दशा
में तब शिथिल की जा सकती
है (हैं) जब चयन के किसी
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा
आयोग की यह राय है कि उनके
लिए अरक्षित रिक्तियों को
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव
रखने वाले अभ्यर्थियों के
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय:—मत्स्य गियर प्रौद्योगिकी में अनुभव।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ
नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

(11)

(12)

33.33 प्रतिशत प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
पर स्थानांतरण द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती।

33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत
अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती
द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसा मातृस्यकी वैज्ञानिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित
सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा
भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालय/
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/मान्यता प्राप्त अनुसंधान
संस्थाओं या परिषदों/अर्ध-सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों
के अधीन ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदुप पद धारण किए हुए
है; या

(ii) जिन्होंने 2200—4000 रु. या समतुल्य वेतन-
मान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की
है; या

(iii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतन-
मान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की
है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति
की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रति-
नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके

(12)

अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति/संविदा पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—
—सदस्य
 3. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण—सदस्य
- समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)।

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
—अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण—सदस्य

टिप्पण्यः—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं. 2-27/92-एफ वाई (प्रशा०)]

ओ. पी. जैन, अवर सचिव

टिप्पण्यः—मख नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i), तारीख 15 अगस्त, 1987 में सा. का. नि. 823 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 29th August, 1995

G.S.R. 429.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension), Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 1987, namely :—

- (i) These rules may be called the Fishery Survey of India Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries

Scientist (Monitoring & Extension)/Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension), Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 1987, for serial number 1 relating to the post of Senior Fisheries Scientist and the entries relating thereto/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension) the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
“1. Senior Fisheries Scientist	15* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.	Selection
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
6	7	8	9	
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes.	Essential :— (i) Master's Degree in Zoology or Marine Biology or Fisheries Management or Oceanography of a recognised University or equivalent. OR Post-Graduate Diploma in the Fisheries Science of the Central Institute of Fisheries Education, Bombay or equivalent; and (ii) 5 years experience in Survey or research of Marine Fisheries including cruise planning and participation in voyages. Note :—(1) The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note :—(2) The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing	Age :—No. Educational Qualifications :— Yes.	

requisite experience are not likely to be available for filling up the vacancies reserved for them.

Desirable:—

Experience in Fishing Gear Technology

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Transfer and percentage of the vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made
10	11	12
1 year for direct recruits	33.33% promotion failing which by transfer on deputation including short term contract. 33.33% direct recruitment. 33.33% transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion :— Fisheries Scientist with 5 years regular service in the grade. Transfer on Deputation (including short term contract) :— Officers under Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Indian Council of Agriculture Research/Recognised Research Institutions or Councils/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 5 years regular service in the posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; and, (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. Note :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries—Member 3. Director General, Fishery Survey of India—Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries—Chairman. 2. Director General, Fishery Survey of India—Member. “Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.”	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation/contract.

[No. 2 27/92-Fy (Admn.)

O.P. JAIN, Under Secy.

Note : Principal Rules were published vide G.S.R. 623 of the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) on 15th August, 1987.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त 1995

सा.का.नि. 430 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संलग्न अनुबंध में उल्लिखित भर्ती नियमों का अधिक्रमण करने हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पूर्व किया गया है या करने में लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वर्ग (ए) और वर्ग (बी) राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—
इन नियमों का संक्षिप्त नाम

(i) केंद्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वर्ग (ए) और वर्ग (बी) राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 1995 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्त पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति

जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्कासे गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

टिप्पणी :

निम्न पदों के मुख्य नियम भारत के राजपत्र में निम्न प्रकार प्रकाशित किए गए थे।

(i) मूल्यांकक (पत्राचार पाठ्यक्रम) सा.का. नियम 206 दिनांक 10-2-79 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 345 तारीख 5-4-82 द्वारा संशोधन किया गया था।

(ii) सहायक शिक्षा अधिकारी (क्षेत्रीय भाषा) सा.का.नियम 710 तारीख 3-6-1978 तथा बाद में उनमें सा.का.नि. 721 दिनांक 28-8-82 और सा.का. नियम 859 तारीख 13/14-10-1988 के अनुसार संशोधन किया गया था।

(iii) सहायक शिक्षा अधिकारी (पत्राचार पाठ्यक्रम) सा.का. नियम 887 तारीख 19-6-76 तथा बाद में सा.का. नियम 225 तारीख 11-02-1978 के अनुसार संशोधन किया गया था।

- (iv) सहायक सिका अधिकारी (सामान्य) सा.का. नियम 53 तारीख 10-1-1976 ।
- (v) वैज्ञानिक अधिकारी—सा.का. नियम 50 तारीख 10-1-1976 ।
- (vi) सहायक निदेशक—सा.का. नियम 298 तारीख 15-3-1977 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 675 तारीख 7-8-82, सा.का. नियम 690 तारीख 17-9-83 तथा सा.का. नियम 64 तारीख 28-11-84 के अनुसार संशोधन किया गया था ।
- (vii) क्षेत्रीय अधिकारी—सा.का. नियम 119 तारीख 8-1-1963 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 379 तारीख 13-04-1986 के अनुसार संशोधन किया गया ।
- (viii) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)—सा.का. नियम 917 तारीख 6-9-1980 ।
- (ix) उप निदेशक—सा.का. नियम 462 तारीख 2-4-1977 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 205 तारीख 10-2-79 सा.का. नियम 500 तारीख 28-5-81 तथा सा.का. नियम 797 तारीख 28-7-84 के अनुसार संशोधन किया गया था ।
- (x) प्रधान संपादक—सा.का. नियम 410 तारीख 13-3-1961 ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या प्रप्रवरण पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रुत है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षित अन्य प्रवृत्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अहताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 प्रधान संपादक (हिंदी)	01@	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' राजपक्षित परिवर्तन हो सकता है ।	रु. 3000-100-3500-125-5000	प्रवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती-पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में के श्रेणियों जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है और उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	<p>पदोन्नति : उपनिदेशक (भाषा) के पद पर नियुक्ति के बाद निर्धारित वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) :</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वाम्यश संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सश्रम पद धारक हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने रुपये 3000-4500 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शर्तों और अनुभव वाले व्यक्ति :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रहा हो; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रहा हो।</p> <p>(ii) 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव समेत हिंदी/संस्कृत/भाषा विज्ञान/कोश विज्ञान में 7 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>फीडर वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधे हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।</p>	<p>ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 3. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य 3. संयुक्त सचिव/संयुक्त-शिक्षा सलाहकार (भाषा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य 4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य 	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(12)

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तों को पात्र नहीं माना जाएगा।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु-सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप-निदेशक (भाषाएं)	06(@) 1995 @कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' राजपक्षित	रु. 3000-100-3500-125-4500	प्रवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	<p>पदोन्नति : सहायक निदेशक (भाषाएं) के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद निर्धारित वेतन-मान में 5 वर्ष की सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सवृण पद धारक हैं; या (ii) जिन्होंने रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने रुपये 2000-3500 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताओं और अनुभव वाले व्यक्ति : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रहा हो या</p>

12

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रहा हो।

- (2) 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव समेत हिंदी/संस्कृत/भाषा विज्ञान/कोश विज्ञान में 5 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।

फीडर वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधे हस्ताक्षर हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तियों को पात्र नहीं माना जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य गवर्ग वाला पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

(13)

(14)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. गवर्नर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
3. संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. उप-निदेशक (विषय)	02* 1995	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए'	र. 3000-100- 3500-125- 4500	प्रवर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	राजपत्रित						

(10)

(11)

(12)

लागू नहीं।

पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।

पदोन्नति :

महायक निदेशक (विषय) के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद निर्धारित वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत)

केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण हैं; या

(2) जिन्होंने रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने 2000-3500 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की निम्नलिखित सेवा की है, और

(ख) निम्नलिखित शर्तों और अनुभव वाले व्यक्ति :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष में संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में इंजीनियरी, कृषि या चिकित्सा शास्त्र, यथा बी आई एम एस/बी ए एम एस में डिग्री या फार्मैसी/आयुर्वेद में डिप्लोमा या समकक्ष।

(2) सैकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी और हिंदी विषयों का अध्ययन।

(3) डिग्री/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण/तकनीकी लेखों या पुस्तकों के लेखन और/या अनुवाद या दोनों से संबंधित शब्दावली कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।

(13)

(14)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर म्यां-
तांतरण/संवैदा पर नियुक्ति करते समय संबंध
लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
3. संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक निदेशक (भाषाएं)	15* 1995 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' राजपत्रित अतिथिक वर्गीय	रु. 2200-75-2800-द.गो.-100-4000	प्रवरण	35 वर्ष से अधिक नहीं* *(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छुट दी जाएगी)।

टिप्पणी:—आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-तिथि को माना जाएगा (न कि उस अंतिम तिथि को जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम जम्मु एवं कश्मीर का लद्दाख डिबीजन, हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला और चंभा जिला का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
सही	अतिरिक्त :	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष और पदोन्नतों के लिए दो वर्ष ।
	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या संस्कृत में मास्टर डिग्री या समकक्ष या भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी साहित्य का विषय के रूप में अध्ययन । (2) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी भाषा का अध्ययन (3) डिग्री/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण/तकनीकी लेखों या पुस्तकों में लेखन और/या अनुवाद या दोनों में संबंधित शब्दावली कार्य का 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (1) हिंदी भाषा के उपयोग में सर्वाधिक कांश विज्ञान कार्य का अनुभव । (2) हिंदी को छोड़कर कम से कम एक प्राथमिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी को छोड़कर कम-से-कम एक विदेशी भाषा का ज्ञान । टिप्पणी : 1. अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के संश्लेष में संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा से अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । 2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के बारे में अर्हता के लिए छूट दे सकता है । यदि चयन की किसी भी अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उनके लिए सुरक्षित किए गए स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे ।		

(11)	(12)
75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अल्पावधि संबंधित समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 25 प्रतिशत अल्पावधि संबंधित समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : सहायक शिक्षा अधिकारी (भाषा) के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् निर्धारित बेतनमान में 5 वर्ष की सेवा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संबंधित समेत) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर सर्वश्रेष्ठ पद धारक हैं; या (2) जिनकी आय 2000-3200 या समकक्ष बेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या (3) जिनकी आय 1640-2900 या समकक्ष बेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) कॉलम 8 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले फीडर वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधे हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

उसी प्रकार पदोन्नति और नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तों को पात्र नहीं माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य सर्वग्न यात्रा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अन्यथावि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अविम-तिधि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)।

(13)

(14)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)।

प्रत्येक नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषा)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—सदस्य
3. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य
4. निदेशक (भाषा)/उप सचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—सदस्य

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचार के लिए)

1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषाएं)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—अध्यक्ष
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य
3. निदेशक (भाषाएं) उपसचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—सदस्य

टिप्पणी : सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के स्थायीकरण में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे। यदि, इन पर आयोग अनुमोदन नहीं देता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस के सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की एक और बैठक बुलाई जाएगी।

1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक निदेशक (विषय)	11* *1095 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ए' राजपत्रित अल्पिक वर्गीय	रु. 2200-75- 2800-र. ग्रे.- 100-4000	प्रमर्श	35 वर्ष से अधिक नहीं* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की 5 वर्ष की छूट दी जाएगी)	वहीं

टिप्पणी :—आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निम्नलिखित विधि (जार्ज में उम्मीदवारों से प्राथमिकता प्राप्त होने की अंतिम-विधि को माना जाएगा (यदि उस अंतिम विधि को जो असम, मेघालय, प्रकणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिनिदाद, जम्मु एवं कश्मीर का लद्दाख डिबीजत हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला और चुरा जिला का पार्मा सब-डिबीजत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या सशर्दीप के उम्मीदवारों के नियमित की गई है।)

टिप्पणी :

1. अन्य प्रकार से बाध्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की प्रकटा में प्रवृत्तियों में कूटनी या मक्ली है।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अलजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के बारे में कूटनी के लिए कूटनी ले सकता है। यदि कूटनी की किसी भी प्रकटा पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन अनुसूचितों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उनके लिए सुरक्षित किए गए स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे।

(8)	(9)	(10)
अतिशय :	वहीं	सीधी प्रतीक्षाओं के लिए एक वर्ष और पदोन्नति के लिए दो वर्ष
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष या		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंजीनियरी, कृषि या चिकित्सा शास्त्र या बी.आर्.एस.एस/बी.ए.ए.एस. में डिग्री या या फार्मसी/आयुर्वेद में डिप्लोमा या समकक्ष।		
(2) सैक्रेटरी स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषयों का अध्ययन		
(3) डिग्री/डिप्लोमा/कक्षाओं के शिक्षण/तकनीकी लेखों या पुरस्कारों के लेखन और/या अनुवाद या दोनों में संबंधित		
सहायकी कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।		
बाधनीय :		
(1) हिंदी भाषा के उपयोग से संबंधित कोण दिशा-निर्देशों का अनुभव।		

(8)

- (2) हिंदी को छोड़कर कम-से-कम एक आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी को छोड़कर कम-से-कम एक विदेशी भाषा का ज्ञान।

(11)

- 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अत्यावधि सचिव समेत प्रतिनियुक्तित्व पर स्थानांतरण द्वारा।
दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
50 प्रतिशत अत्यावधि सचिव समेत प्रतिनियुक्तित्व पर स्थानांतरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

पदोन्नति :
सहायक शिक्षा अधिकारी (विषय) के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् निर्धारित वेतनमान से 5 वर्ष की सेवा।

प्रतिनियुक्तित्व पर स्थानांतरण (अत्यावधि संविदा समेत)
केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (1) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारक हैं; या
(2) जिन्होंने रुपये 2000-3200 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या
(3) जिन्होंने रुपये 1640-2800 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और
(ख) कम से 8 मंसीपी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधे हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्तित्व द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तियों की पात्र नहीं माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्तित्व की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य सेवर्ग वांछ्य पद पर प्रतिनियुक्तित्व की अवधि सम्मिलित है, समाप्त: चार वर्ष के क्रमिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्तित्व पर स्थानांतरण (अत्यावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आठ सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-तिथि के दिन 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(13)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य—सब लोक सेवा आयोग -- अध्यक्ष
2. उपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषाएं)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) -- सदस्य
3. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय -- सदस्य
4. निदेशक (भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) -- सदस्य

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचार के लिए)

1. उपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषाएं)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) -- अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय -- सदस्य
3. निदेशक (भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) -- सदस्य

(14)

प्रत्येक नियुक्ति के समय सब लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(13)

टिप्पणी :- सीबी सर्ती वाले अधिकारियों के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के कार्यबल अनुसोदन के लिए आवेग को लेजे जाएंगे। यदि इन पर आयोग अनुसोदन नहीं देता तो सब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की एक और बैठक बुलाई जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक शिक्षा अधिकारी (भाषा)	23* 1995 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साक्षात्कार केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित असिपिक वर्गीय	स. 2080-60- 2300-50-710 75-3200	अप्रवर्ण	भाग नहीं	नहीं
(8)	(9)		(10)			
भाग नहीं	नहीं		भाग नहीं			

(11)	(12)
प्रवर्धन द्वारा और गुमान होने पर अध्यापक संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	<p>प्रवर्धन :</p> <p>अनुसंधान सहायक (हिंदी) अनुसंधान सहायक (क्षेत्रीय भाषाएं) मूल्योक्त (पत्राचार पाठ्यक्रम) और मूल्योक्त (क्षेत्रीय भाषाएं) के पद पर नियुक्ति के बाद निर्धारित वेतनमान में दो वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पणी :- प्रवर्धन के लिए पात्रता सूची अधिकांश द्वारा संबंधित वेतनमान/वर्ग के लिए निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि के संबंध में तैयार की जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अध्यापक संविदा समेत) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (1) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारक है; या</p> <p>(2) जिन्होंने रुपये 1640-2900 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(3) जिन्होंने रुपये 1400—2300/2600 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताओं और अनुभव वाले व्यक्ति :</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री या संस्कृत में मास्टर डिग्री या समकक्ष या</p> <p>भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री और उसके साथ डिग्री स्तर पर हिंदी साहित्य का विषय के रूप में अध्ययन।</p> <p>(2) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी का विषय के रूप में अध्ययन।</p> <p>(3) डिग्री/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण तकनीकी लेखों या पुस्तकों के लेखन और/या अनुवाद या दोनों से संबंधित शैक्षणिक कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>फीडर वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो प्रवर्धन के लिए सीधे हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए भाग नहीं माना जाएगा।</p>

(12)

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तियों को प्राप्त नहीं माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संबंध बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से प्राप्ति-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-निधि के विम 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(13)

यू.ए. 'बी' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए)

1. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय —अध्यक्ष

2. निदेशक (भाषाएं) उच्च सचिव (भाषाएं)/ उप शिक्षा सहायक (भाषाएं), शिक्षा विभाग या उनका उपयुक्त पद भावा मामिति —सदस्य

3. सचिव, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/प्रधान संपादक केन्द्रीय हिंदी निदेशालय —सदस्य

(14)

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्ति करने समय संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक शिक्षा अधिकारी (विषय)	७४* (1995) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित	₹. 2000-60-2300-२. री.-75-3200	अप्रवर्ण	नागू नहीं	उसी
(8)				(9)		(10)
नागू नहीं				नहीं		नागू नहीं

(11)

पदोन्नति द्वारा और सेवा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा

(12)

पदोन्नति :

अनुसंधान सहायक (विषय) के पद पर नियुक्ति के बाद निर्धारित वेतनमान में दो वर्ष की सेवा।

टिप्पणी :—पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा संबंधित वेतनमान पद के लिए निर्धारित श्रेष्ठ सेवा पूर्ण करने की तिथि के संबंध में तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (1) जो नियमित आधारे पर सदृश पद धारक हैं; या
- (2) जिन्होंने रुपये 1640—2900 या समकक्ष वेतनमान के पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या
- (3) जिन्होंने रुपये 1400—2300/2600 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और

(12)

(क) निम्नलिखित श्रेणियों और अनुभव वाले व्यक्ति :—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष
या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में इंजीनियरी, कृषि या चिकित्सा शास्त्र, या बी.आर.एम.एम./बी.ए.एम.एम. डिग्री या फार्मेशन/फार्मस्यूट से डिप्लोमा या समकक्ष

या

भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री और उसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी साहित्य का विषय के रूप में अध्ययन।

(2) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी का विषय के रूप में अध्ययन।

(3) डिग्री/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण/तकनीकी लेखों या पुस्तकों के लेखन और/या अनुवाद या दोनों में संबंधित गव्वावली कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

फॉरवर्ड वर्क के दो विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए भीड़े हुए हैं उन्हें प्रतिनिधित्व द्वारा निर्दिष्ट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनिधित्वों को पात्र नहीं माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करते पर अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदनपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(13)

(14)

ग्रुप 'बी' विभागीय प्रोमोति समिति (पदोन्नति के लिए) :

1. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली शायीय निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
---सदस्य2. निदेशक (भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), शिक्षा विभाग या उनका उपयुक्त पद वाला समिति
---सदस्य3. सचिव, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली प्रायोग प्रधान संपादक केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
---सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/सविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. मूल्यांकक (पत्राचार पाठ्यक्रम)	27* 1995 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	र. 1640-60-2600-द. रो.-75-2900	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या निदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छुट दी जाएगी)	नहीं

(8)	(9)	(10)
प्रतिवार्य :	नहीं	दो वर्ष
<p>(i) किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी का विषय के रूप में अध्ययन।</p> <p>या</p> <p>किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी का विषयों के रूप में अध्ययन</p>		
<p>(ii) द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का कम-से कम दो वर्ष का अनुभव</p>		
वांछनीय :		
<p>(i) हिंदी के प्रतिरिक्त किसी प्राथमिक भारतीय भाषा का ज्ञान</p>		
<p>(ii) किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष</p>		
<p>(iii) किसी माध्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित भाषा विज्ञान/भाषा शिक्षा प्रशिक्षण में प्रशिक्षण या भाषी-दारी।</p>		
टिप्पणी :		
<p>1. अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा से अर्हताओं से छूट दी जा सकती है।</p> <p>2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के बारे में अर्हता के लिए छूट दे सकता है। यदि चयन की किसी भी अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उनके लिए सुरक्षित किए गए स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे।</p>		
(11)	(12)	
सीधी भर्ती :	नाग, नहीं	
टिप्पणी :		
<p>एक वर्ष या अधिक अवधि तक पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अग्रयानाचर छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण हुए रिक्त पदों को नियुक्ति अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से भर सकता है:</p>		
<p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारक है या रु. 1400-2300/2800 या समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं; और</p>		
<p>(ख) जो कालम 8 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p>		
<p>टिप्पणी :—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति करने के लिए अधिक आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
<p>टिप्पणी :—आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को माना जाएगा (न कि उस अंतिम तिथि को जो अंतिम, मेघालय,</p>		

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख़ डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का स्पीति जिला और चम्पा जिला का पांसी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पाल्हाद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई ।

(13)

(14)

ग्रुप 'बी' विभागीय प्रोन्नति/समिति (स्थायीकरण के लिए)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

1. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय —अध्यक्ष
2. निदेशक (भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उपयुक्त पदवाला उनका नामिति —सदस्य
3. प्रधान संपादक केन्द्रीय हिंदी निदेशालय —सदस्य
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों समुदाय का ग्रुप 'ए' अधिकारी —सदस्य

टिप्पणी :—सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के कार्यभर अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे । यदि इन पर आयोग अनुमोदन नहीं देता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की एक और बैठक और बुलाई जाएगी ।

अनुलग्नक

- वे भर्ती नियम जिनका अतिक्रमण किया जाना है
1. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, प्रधान संपादक भर्ती नियम-1961 ।
 2. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उपनिदेशक (उपनिदेशक प्रशासन को छोड़कर) भर्ती नियम 1977 ।
 3. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, उपनिदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 1980 ।
 4. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, क्षेत्रीय अधिकारी भर्ती नियम, 1986 ।
 5. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, सहायक निदेशक भर्ती नियम, 1977 ।
 6. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक अधिकारी (इंजीनियर) भर्ती नियम, 1976 ।
 7. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी (सामान्य) भर्ती नियम 1976 ।
 8. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी एवं मूल्यांकक (पत्राचार (पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 1976 ।
 9. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी एवं मूल्यांकक (क्षेत्रीय भाषाएं) भर्ती नियम, 1982 ।

सं. एफ. 2-16 88— प्रज्ञा .

जे. एल. सहगल, उप निदेशक (भाषाएं)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 30th August, 1995

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in super session of the Recruitment Rules mentioned in the Annexure enclosed hereto except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts. The Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 1995.

- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and qualifications.—The method of recruitment of the said posts, age limit educational qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No Person ,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

NOTE :

The Principal Rules of the following posts were Notified and Published in the Government of India Gazette as under :

- (i) Evaluator (Correspondence Course) Vide GSR No. 206 dated 10-02-1979 and amended vide GSR No. 345 dated 05-04-82.
- (ii) Assistant Education officer (Regional Languages) vide GSR No. 710 dated 03-06-1978 and amended vide GSR No. 721 dated 28-08-82 and GSR No. 859 dated 13/14-10-1988.

(iii) Assistant Education Officer (Correspondence Course) Vide GSR No. 887 dated 19-06-76 and amended vide GSR No. 225 dated 11-02-1978.

(iv) Assistant Education Officer (General vide GSR No. 53 dated 10-01-1976.

(v) Scientific Officer vide GSR No. 50 dated 10-01-76.

(vi) Assistant Director vide GSR No. 298 dated 05-03-1977 and amended vide GSR No. 675 dated 07-08-82, GSR No. 690, dated 17-09-83 and GSR No. 64 dated 28-11-84.

(vii) Regional Officer vide GSR No. 119 dated 08-01-1963 and amended vide GSR No. 379 dated 13-04-86.

(viii) Dy. Director (Correspondence Course) vide GSR No. 917 dated 06-09-80.

(ix) Dy. Director vide GSR No. 462 dated 02-04-1977 and amended vide GSR No. 205 dated 10-02-79, GSR No. 500 dated 28-05-81 and GSR No. 797 dated 28-07-84.

(x) General Editor vide GSR No. 410 dated 13-03-1961.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. General Editor (Hindi)	01	General Central Services Group A, Gazetted	Rs. 3000-100-3500-125-5000	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
*1995 Subject to variation dependent on workload							
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods					
9	10	11					
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short-term contract.					
				12			
				Promotion: Deputy Director (Language) with 2 years regular service in the Grade. Transfer on deputation (Including short term contract)			

Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or
- (ii) With 2 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 3000-4500 or equivalent; or
- (iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200-4000 or equivalent, and
- (b) Possessing following qualifications and experience:
 - (i) Master's Degree in Hindi from a recognised university or equivalent

OR

Master's Degree in Sanskrit with Hindi as one of the subjects of study at Degree or Master's level from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Linguistics with Hindi as subjects of study at degree or Master's Level from a recognised university or equivalent.

- (ii) Seven years experience of research in Hindi/Sanskrit/Linguistics/ Lexicography including three years Administrative Experience

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

13

14

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)

1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman.
2. Secretary, M/O Human Resource Development—Member.
3. Joint Secretary/Joint Education Advisor (Language) M/O Human Resource Development—Member
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Deputy Director (Languages) @06

General
Central
Services
Group A.
Gazetted

Rs. 3000-
100-3500-
125-4500

Selection

Not appli-
cable

Not appli-
cable

Not appli-
cable

@1995

Subject to variation dependent on workload.

9

10

11

12

Not applicable

Not applicable

Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.

Promotion :

Assistant Director (Languages) with five years regular service in the grade.

Transfer on deputation (Including short-term contract)

Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):

(a) (i) Holding analogous post on regular basis; or

(ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or

(iii) With 8 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and

(b) Possessing following qualifications and experience :

12

(i) Master's Degree in Hindi from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Sanskrit with Hindi as one of the subjects of study at Degree or Master's level from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Linguistics with Hindi as subjects of study at degree of Master's Level from a recognised university or equivalent.

(ii) 5 years experience of research in Hindi/Sanskrit/Linguistics/Lexicography including three years Administrative Experience.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

13

14

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)

1. Chairman/Member-Union Public Service Commission—Chairman.
2. Secretary, M/O Human Resource Development—Member
3. Joint Secretary/Joint Education Advisor (Language) M/O Human Resource Development—Member
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Deputy Director (Subjects)	02@ @ (1995) Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group A, Gazetted	Rs. 3000- 100-3500- 125-4500	Selection	Not appli- cable	Not appli- cable	Not appli- cable
9	10	11	12				
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation in- cluding short term contract.	<p>Promotion : Assistant Director (Subjects) with five years regular service in the grade. Transfer on deputation (Including short term contract)</p> <p>Officers under the Central/State Govern- ment/Autonomous Organisations (in- cluding Universities and Research Ins- titutions):</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200- 4000 or equivalent; or</p> <p>(iii) With 8 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing following qualifications and experience;</p> <p>(i) Master's Degree in the subject concerned from a recognised uni- versity or equivalent</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Degree in Engg. Agriculture or Medicine i.e. BIMS/ BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from a recognised university/ board or equivalent.</p> <p>(ii) English and Hindi as subjects of study at Secondary Level.</p> <p>(iii) 5 years experience of Teach- ing degree/Diploma classes/ Terminological work on writing technical articles or books and/or translation of both.</p>				

13

14

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Secretary, M/O Human Resource Development—Member
3. Joint Secretary/Joint Education Adviser (Language) M/O Human Resource Development—Member
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/
Director, Central Hindi Directorate—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation contract.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Director (Languages)	15* 1995 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group A, Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75- 2800-EB-100- 4000	Selection	Not exceeding 35 yrs. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govern- ment). Note : The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candida- tes in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Essential : (i) Master's Degree in Hindi or Sanskrit of a recognised university or equivalent OR Master's degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at Degree Level. (ii) English as one of the subjects of study at Degree Level. (iii) 3 years experience of Teaching Degree/Diploma classes/Terminological work on writing technical articles of Books and/or Translation or both. Desirable : (i) Experience of Lexicogra- phical work involving use of Hindi.	No	1 year for direct recruits & 2 years for promo- tees.	75.00% promotion failing which by transfer on depu- tation including short term contract). Failing both by direct recrtt. 25.00% transfer on deputa- tion including short term contract failing which by direct recruit- ment.

(8)

- (ii) Knowledge of atleast one modern Indian Language other than Hindi and one Foreign Language other than English.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

<p>Promotion : Assistant Education Officer (Language) with five years regular service in the grade. Transfer on deputation (including short term contract). Officers under the Central/State Government/ Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions): (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3200 or equivalent; or (iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion): 1. Chairman/Member—Union Public Service Commission—Chairman. 2. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Language) Ministry of Human Resource Development (Department of Education)—Member. 3. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member 4. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission on necessary each occasion.</p>
<p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation): 1. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Languages) Ministry of Human Resource Development (Department of Education)—Chairman 2. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member 3. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Adviser (Languages), Ministry</p>	

(12)	(13)
department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	of Human Resource Development (Department of Education)—Member “Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Director (Subjects)	11* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group A, 2800-EB-100-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-4000.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K Spiti district and Pangl Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Essential : (i) Master's Degree in Subject concerned from a recognised university or equivalent. OR Degree in Engg., Agriculture or Medicine i.e. BIMS/BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from recognised university/board or equivalent (ii) English and Hindi as subjects of study at Secondary Level. (iii) 3 years experience of Teaching Degree/Diploma classes/Terminological work on writing technical articles or Books and/or Translation or both. Desirable : (i) Experience of Lexicographical work involving use of Hindi.	No	1 year for direct recruits & 2 years for promotees.	50.00 % Promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract) Failing both by direct rectt. 50.00 % Trasfer on deputa- tion including short term contract failing which by direct recruitment.

(8)

- (ii) Knowledge of atleast one modern Indian Language other than Hindi and one Foreign Language other than English.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

Promotion:
Assistant Education Officer (Subjects) with five years regular service in the grade.
Transfer on deputation (including short-term contract)
Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions) :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
(ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3200 or equivalent; or
(iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; and

- (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

Group A Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman/Member—Union Public Service Commission—Chairman
2. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Language) Ministry of Human Resource Development (Department of Education).—Member
3. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member
4. Director (Languages)/ Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary each occasion.

Group 'A' Departmental Promotion Committee
For considering confirmation):

1. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Languages) Ministry of Resource Development, Department of Education) Chairman.
2. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director Central Hindi Directorate—Member.
3. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member.

"Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be over by the Chairman or a Member" of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Education Officer (Languages)	22* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
No	Not applicable	No	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	
(12)	(13)	(14)			
<p>Promotion: Research Assistant (Hindi), Research Assistant (Regional Languages), Evaluator (Correspondence Courses) and Evaluator (Regional Languages) with two years regular service in the grade. Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective Grade/Post. Transfer on deputation (including short term contract): Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) With 2 years' regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; or</p> <p>(iii) With 7 years' regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing following qualifications and experience:</p> <p>(i) Master's Degree in Hindi or Sanskrit of a recognised university or equivalent OR Master's Degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at Degree Level.</p> <p>(ii) English as one of the subjects of study at Degree Level.</p> <p>(iii) 2 years' experience of Teaching degree/Diploma classes/Terminological work on writing teaching articles or books and/or translation or both.</p> <p>The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (For promotion):</p> <p>1. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Chairman</p> <p>2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/Deputy Educational Adviser (Languages), Department of Education or his nominee of appropriate status—Member</p> <p>3. Secretary, Commission for Scientific and Technical Terminology/General Editor, Central Hindi Directorate—Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Assistant Education Officer (Subjects)	8* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group B. Gazetted	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
No	Not applicable	No	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	
(12)	-	(13)	(14)		
Promotion : Research Assistant (Subjects) with two years regular service in the grade. Transfer on deputation (including short term contract) Officers under the Central/State Government/ Autonomous Organisation (including Universities and Research Institutions) : (a) (i) Holding, analogous post on regular basis; or (ii) With 2 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 1640—2900 or equivalent; or (iii) With 7 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 1400—2300/2600 or equivalent, and (b) Possessing following qualifications and experience : (i) Master's Degree in the subject concerned from a recognised university or equivalent OR Degree in engineering, Agriculture or Medicine i.e. BIMS/BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from a recognised university or equivalent. OR Master's Degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at degree level. (ii) English as one of the subjects of study at degree level. (iii) 2 years experience of Teaching degree/ Diploma classes/Terminological work on writing teaching articles or books and/or translation or both.		Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Chairman 2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Department of Education or his nominee of appropriate status—Member 3. Secretary, Commission for Scientific and Technical Terminology/General Editor, Central Hindi Directorate—Member		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.	
The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.					

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Evaluator (Correspondence Courses)	27* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable	Not Exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Essential :	No	2 years	Direct recruitment.
	(i) Master's Degree in Hindi with English as a subject of study at Degree Level from a recognised university or equivalent. OR Master's Degree in Linguistics with Hindi and English as subject of study at Degree Level from a recognised university or equivalent.			Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on Deputation or Long illness or Study Leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis by the appointing authority from officers of Central Government:
	(ii) At least 2 years experience of teaching Hindi as a second language.			(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or with 5 years Regular Service in posts in the scale of Rs. 1400—2300/2600; and (b) Possessing the qualification & experience prescribed for Direct recruits under column 8.
	Desirable :			Note : The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
	(i) Knowledge of any Modern Indian Language other than Hindi.			Note : The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)

(ii) Degree or Diploma of a recognised university or equivalent in Education with specialisation in Hindi Teaching

(iii) Training or Participation in Linguistics/Language Teaching Training conducted by a recognised Institute/university.

Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note : 2. The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

Not applicable

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

1. Director Central Hindi Directorate—Chairman.
2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages) Ministry of Human Resources Development or his nominee of appropriate status—Member
3. General Editor, Central Hindi Directorate—Member
4. Group 'A' officer belonging to Scheduled cast/Scheduled tribe Community—Member

“Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.”

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

ANNEXURE

The Recruitment Rules sought to be superseded:—

1. Central Hindi Directorate General Editor Recruitment Rules, 1961.

2. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Recruitment Rules for the post of Deputy Director (other than Deputy Director Administration) 1977.

3. Central Hindi Directorate Recruitment Rules for Deputy Director (correspondence Courses) 1980.

4. Central Hindi Directorate Regional officer Recruitment Rules, 1986.

5. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Assistant Director Recruitment Rules, 1977.

6. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Scientific officer (Engineering) Recruitment Rules, 1976.

7. Central Hindi Directorate, Assistant Education officer (General) Recruitment Rules, 1976.

8. Central Hindi Directorate Assistant Education officer and Evaluators (Correspondence Courses) Recruitment Rules, 1976.

9. Central Hindi Directorate Assistant Education officer and Evaluators' (Regional Language) Recruitment Rules, 1982.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1995

सांकांनि० 431.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1993 नामक कतिपय मसौदा नियम भारत के राजपत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय सं० सांकांनि० 575 दिनांक 27 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना के साथ इनसे प्रभावित होने वाले सम्भावित किसी भी व्यक्ति से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन के अंदर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि, उक्त मसौदा नियम शासकीय राजपत्र में 19 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि, मसौदा नियम की राजपत्र प्रतियां, जिनमें वे प्रकाशित किए गए थे, 19 नवम्बर, 1994 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी।

और जबकि, इनसे प्रभावित होने वाले किसी भी सम्भावित व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 के अधिक्रमण

2194 GI/95-6

में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा करने से रह गए कार्यों के सिवाए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श के उपरान्त एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

प्रारंभिक:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली, 1995 है।

2. ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “लेखा अधिकारी” से अभिप्रेत है वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या अन्य ऐसा अधिकारी जिसे इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

(ख) “अधिनियम” से अभिप्रेत है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34);

(ग) “निगम” से अभिप्रेत है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

(घ) “परिलब्धियों” से अभिप्रेत है मूल नियमों में यथा-परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान और इसमें वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान के अनुरूप महंगाई वेतन यदि स्वीकार्य हो और प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई अन्य पारिश्रमिक भी शामिल है।

(ङ) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त निगम द्वारा नियुक्त किया गया था निगम के स्टाफ के संवर्ग का कोई व्यक्ति;

(च) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है:—

(i) पुरुष अभिदाता की वशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही;

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक् हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, स्वीजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार नहीं रह गई है तो उसे, तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाब में लिखित रूप में यह सूचित न करे

कि उसे उस रूप में जाना जाता रहेगा कि वह उन मामलों में जिसका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है।

- (ii) स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता-पिता, सन्तानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और सन्तानें और जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों वहाँ उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही।

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, जब तक कि अभिदाता बाध में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रह न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण: इस खंड में संतान में अभिप्रेत धर्मज सन्तान है और जहाँ अभिदाता पर लागू स्वीय विधि दत्तक पुत्र ग्रहण को मान्यता देती है वहाँ इसमें दत्तक संतान भी शामिल है:

- (छ) "निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि अभिप्रेत है;
- (ज) "छुट्टी" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी-वृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 द्वारा मान्य कोई भी छुट्टी अभिप्रेत है;
- (झ) "सेवा" से निगम के अधीन सेवा अभिप्रेत है;
- (ञ) "वर्ष" से वित्त वर्ष अभिप्रेत है।

इन नियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का, जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या मूल नियम में परिभाषित है, उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में वह उसमें परिभाषित है परन्तु इसमें परिभाषित न की गई अभिव्यक्ति का अर्थ क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 या यथास्थिति मूल नियमों में यथा-परिभाषित होगा।

3. इन नियमों की कोई बात इस प्रकार से प्रभावी नहीं समझी जाएगी जिससे कि इससे पूर्व विद्यमान भविष्य निधि की विधिमानता समाप्त होती है या कोई नई विधि गठित होती है।

3. निधि का गठन:—

- (1) निधि रुपये में रखी जाएगी।
- (2) इन नियमों के अधीन निधि में जमा की गई सभी राशियाँ "कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि"—नामक निधि में जमा की जाएगी। ऐसी राशियाँ जिनकी अदायगी इन नियमों के अधीन उनके देय हो जाने के पश्चात् छः मास के भीतर प्राप्त नहीं कर ली गई हैं, वर्ष के अंत में जमा लेखा को अन्तरित कर दी जाएगी और उनके संबंध में कार्रवाई जमा राशियों में संबंधित सामान्य नियमों के अधीन की जाएगी।

4. लेखा अधिकारी द्वारा निधि का संचालन:

निधि का संचालन लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इसके द्वारा इन नियमों के अधीन की जाने वाली सभी अदायगियों की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है।

5. निवेश

निधि से संबंधित सभी धनराशि का निवेश कर्मचारी राज्य बीमा निधि से संबंधित धनराशि के निवेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

6. पात्रता की शर्तें

सभी अस्थायी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (उनके विश्व जो अभिदायी भविष्य निधि की सदस्यता के पात्र हैं) और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदान करेंगे।

परन्तु ऐसा कोई कर्मचारी जिससे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान करने की अपेक्षा की गई है या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, निधि में सम्मिलित होने या अभिदाता के रूप में बने रहने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी निधि में अभिदान करने के अपने अधिकार को प्रतिधारित रखता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अस्थायी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1960 से पहले एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुका है, प्रथम अप्रैल, 1960 से पहले की किसी तारीख से निधि में अभिदान नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण:—ऐसा कोई अस्थायी कर्मचारी जो किसी मास के किसी दिन एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है उसके पश्चात्बर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा।

टिप्पणी 1:—इस नियम के प्रयोजन के लिए शिक्षकों और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अस्थायी कर्मचारी माना जाएगा।

टिप्पणी 2:—ऐसा अस्थायी कर्मचारी जो किसी मास के बीच में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है उसके पश्चात्बर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा।

टिप्पणी 3:—ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनमें शिक्षा और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी शामिल हैं। जो नियमित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं और जिनके एक वर्ष से अधिक तक बने रहने की संभावना है एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय सामान्य भविष्य निधि में अभिदान कर सकते हैं।

7. नाम निर्देशन

(1) निधि में सम्मिलित होने के समय अभिदाता लेखा अधिकारी को एक नामांकन भेजेगा जिसके द्वारा निधि में उसके नाम जमा रकम उस रकम के देय होने से पूर्व अथवा देय होने पर अवायगी किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यदि अभिदाता अवयस्क है तो उससे नामनिर्देशन करने की अपेक्षा वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर की जाएगी।

परन्तु यह और कि वह अभिदाता जिसका नामनिर्देशन करने के समय कोई कुटुम्ब है ऐसा नामनिर्देशन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या किसी सदस्यों के पक्ष में करेगा।

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि की भावत किया गया कोई नामनिर्देशन जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदान कर रहा था में उसके नाम में जमा रकम यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाने में अंतर्गत कर दी गई है तो तब तक इस नियम के अधीन किया गया विधिवत् नामनिर्देशन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामनिर्देशन नहीं कर देता।

2. यदि अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामांकन में वह रकम या अंश जो प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय होगी इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत निधि में उसके नाम किसी समय जमा सम्पूर्ण रकम आ जाए।

3. प्रत्येक नामनिर्देशन इन नियमों के साथ सलग अनुसूची-1 में घोषित प्रारूप में किया जाएगा।

4. अभिदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित सूचना भेजकर उस द्वारा किए गए नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक् रूप से इस नियम के उपबंधों के अनुसार नया नामनिर्देशन भेजेगा।

5. अभिदाता नामनिर्देशन में:—

(क) यह व्यवस्था कर सकता है कि यदि उसकी मृत्यु अभिदाता की मृत्यु से पूर्व हो जाए तो विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें नामनिर्देशन में निर्दिष्ट किया जाए अन्तर्गत हो जाएगा।

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब का अन्य कोई सदस्य है तो ऐसे या ऐसे अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य होने चाहिए। परन्तु जहां अभिदाता इस खंड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत नामनिर्देशिती को देय सम्पूर्ण रकम आ जाए।

(ख) यह व्यवस्था कर सकता है कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह व्यवस्था करेगा कि खंड (क) के अधीन किसी वैकल्पिक नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उसके कुटुम्ब में अन्य सदस्य या सदस्यों के आ जाने पर अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने के तुरंत पश्चात जिसके संबंध में नामनिर्देशन में उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है या कोई ऐसी घटना घट जाने पर जिसके कारण नामनिर्देशन उपनियम (5) के खंड (ख) या उसके परन्तुक के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाता अभिदाता नामनिर्देशन को रद्द करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित सूचना देगा और उसके साथ इस नियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और अभिदाता द्वारा किए गए रद्दकरण की प्रत्येक सूचना वहां तक जहां तक कि वह विधिमान्य है उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगी।

टिप्पणी—इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “व्यक्ति” या “व्यक्तियों” के अन्तर्गत कम्पनी या संघ या व्यक्ति निकाय भी होंगे, चाहे वे नियमित हों या न हों। इसमें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि या कोई धर्मार्थ या अन्य न्यास अथवा निधि जैसी ऐसी निधि भी शामिल होगी जिसके लिए नामनिर्देशन भूगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सचिव या उक्त निधि के अन्य प्रशासक या न्यास के माध्यम से किया जा सकता है।

8. अभिदाता का लेखा

विश्वलिखित दशाने के लिए प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जाएगा:—

1. उसके अभिदान
2. अभिदानों पर नियम 13 में यथा-उपस्थित व्याज,
3. निधि में अग्रिम लेना और रकम निकालना।

9. अभिदानों की शर्तें और शर्तें

(1) अभिदाता उस अधि के सिवाय जब यह निर्दिष्ट हो, निधि में प्रतिमास अभिदान करेगा।

परन्तु कुछ अवधि तक निलंबित रहने के पश्चात् बहाल किए जाने पर अभिदाता को उक्त अवधि के लिए देय अभिदान की बकाया रकम की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में करने का विकल्प दिया जाएगा परन्तु यह राशि उस देय अभिदान की बकाया रकम की अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी।

परन्तु यह और कि अभिदाता को अपने विकल्पानुसार ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने की छूट होगी जिसके लिए छुट्टी वेतन न हो या जिसका छुट्टी वेतन आधे वेतन या आधे औसत वेतन से कम हो।

टिप्पणी-1

किसी स्थापना में मौसमी पद के पदधारी द्वारा नियोजन की अवधि के दौरान निधि में अभिदान किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी-2

अभिदाता को छूट दिवस के रूप में समझी जाने वाली अवधि के दौरान अभिदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अभिदाता उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के विकल्प की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा।

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन बिल स्वयं बनाता है तो छुट्टी पर जाने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदान के कारण कटौती न करके;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन बिल स्वयं नहीं बनाता तो छुट्टी पर जाने से पहले अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना विधिवत् और समय पर नहीं दी जाएगी तो यह समझा जाएगा कि अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी :—

इस उप नियम के अन्तर्गत सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

(3) ऐसा अभिदाता जिसने निधि में अपने नाम जमा रकम को नियम-33 के अधीन निकाल लिया है ऐसी रकम निकालने के पश्चात् तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह इयूटी से वापस नहीं आ जाता।

4. उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उस मास के लिए जिसमें वह सेवा छोड़ता है निधि में अभिदान तब तक नहीं करेगा जब तक वह उक्त मास के आरंभ से पूर्व कार्यालय के प्रधान को उक्त मास के लिए अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना नहीं दे वेता।

10. अभिदान की धरें :—

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिदान की दर अभिदाता द्वारा स्वयं नियत की जाएगी, अर्थात्

(क) वह पूर्ण रूपों में की जाएगी।

(ख) इस प्रकार दी गई दर कोई भी ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो।

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अंशदायी भविष्य निधि में 8-1/3 प्रतिशत की उच्च दर से अभिदान करता रहा है अभिदान की दर इस प्रकार से दी गई ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो।

(ग) जब कोई कर्मचारी यथा स्थिति, 6 प्रतिशत या 8-1/3 प्रतिशत की न्यूनतम दर में अभिदान करने का विकल्प देता है तब अभिदान को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और ऐसा करते समय 50 पैसे तथा इससे अधिक को निकटतम पूर्ण रुपये के रूप में गिना जाएगा।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए अभिदाता की परिलब्धियां :—

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में था वही उपलब्धियां होंगी जिनका वह उस तारीख को हकदार था, परन्तु :—

(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को अर्द्ध वेतन छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था अथवा उक्त तारीख को वह निलंबित था तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका कि वह अपनी इयूटी पर लौटने के बाद वह उस तारीख को हकदार था;

(2) यदि अभिदाता उक्त तारीख को, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था अथवा उक्त तारीख को अर्द्ध वेतन छुट्टी पर था और छुट्टी पर रहता है तो उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनका वह इयूटी पर होने या भारत में इयूटी पर होने की दशा में हकदार होता;

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में नहीं था उसकी परिलब्धियां वे होंगी जिनका वह निधि में सम्मिलित होने की तारीख को हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने भासिक अभिदान की रकम नियत करने की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को इयूटी पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल से इस निमित्त या ऐसा करने के लिए करता है;

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी अर्द्ध वेतन छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था या ऐसी तारीख को वह निर्लब्ध था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह छुट्टी पर वापस आने के बाद अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ;

(ग) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और अर्द्ध वेतन छुट्टी पर चलता रहता है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो उस मास के लिए अपने वेतन बिल से इस निमित्त करवाना पड़ता है या करता है ;

(घ) यदि उसने वर्ष के दौरान प्रथम बार सेवा में प्रवेश किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के वेतन बिल से जिस मास से वह निधि में सम्मिलित हुआ है, इस निमित्त करवाना पड़ता है या करता है ।

(4) इस प्रकार नियत की गई अभिदान की रकम —

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकती है ;

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है ;

(ग) यथापूर्वोक्त घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

परन्तु यदि अभिदान की रकम उस प्रकार घटाई जाती है तो वह उप नियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी ।

परन्तु यह और यदि अभिदाता किसी कैलेण्डर मास के किसी भाग में वेतन बिना छुट्टी या अर्द्धवेतन या अर्द्धवेतन छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया है तो अभिदान को देय रकम काम करने के दिनों की संख्या जिसमें उस पर निर्दिष्ट छुट्टियों से भिन्न छुट्टी यदि कोई है, सम्मिलित है, के अनुपात में होगी ।

11. सरकारी या किसी अन्य संगठन या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ।

यदि अभिदाता का स्थानांतरण कर दिया जाता है या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह उसी रीति से निधि के नियमों के अधीन रहेगा मानो उसका स्थानांतरण न हुआ हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर न भेजा गया हो ।

12. अभिदानों की वसूली

(1) यदि परिलब्धियां निधि से ली जाती हैं तो अभिदान की वसूली तथा निधि में से किसी प्रकार की अग्रिम के मूल तथा ब्याज की वसूली परिलब्धियों में से ही की जाएगी ।

(2) यदि परिलब्धियां किसी अन्य स्त्रोत से ली जाती हैं तो अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास लेखा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु सरकार के स्वामित्वधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदानों के मामले में अभिदानों की वसूली ऐसे निकाय द्वारा की जाएगी और वह लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(3) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से जिसका निधि में सम्मिलित होने की उससे अपेक्षा की गई है, अभिदान नहीं करता या किसी वर्ष के दौरान किसी मास अथवा कई मासों में नियम-9 में उपबन्धित में भिन्न स्थिति में अभिदान करने में चूकता है तो अभिदान की वकाया मद्धे निधि में देय कुल रकम नियम-13 में उपबन्धित दर से ब्याज सहित अभिदाता अविलम्ब निधि में अदा की जाएगी या चूकने पर लेखा अधिकारी उस रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से किन्हीं में अथवा अन्यथा जैसाकि वह प्राधिकारी, जो ऐसी अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम है, जिसकी मंजूरी के लिए नियम-14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, निर्देश करे, कटौती करके वसूली करने के आदेश देगा ।

परन्तु उन अभिदाताओं में, जिनकी निधि में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, कोई ब्याज अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

13. ब्याज

(1) उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम अभिदाता के खाते में ब्याज ऐसी दर से जमा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाए ।

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित ब्याज की दर चार प्रतिशत से कम है तो जिस वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रथम बार चार प्रतिशत से कम नियत की गई है, उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में निधि के सभी अभिदाताओं को चार प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि उस अभिदाता को भी, जो पहले केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था और जिसके अभिदान उन पर ब्याज सहित नियम-26 के अधीन इस निधि में उसके लेखों में अन्तर्गण कर दिए गए हैं, चार प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा । यदि वह इस नियम के प्रथम परन्तुक के समान किसी उपबन्ध के अधीन एसी अन्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उस दर पर ब्याज प्राप्त कर रहा था ।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा :—

(1) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के जमा खाते रकम पर, उसमें चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर बारह मास के लिए ब्याज ;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर चालू वर्ष के आरंभ से रकम निकालने के मास के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक के लिए ब्याज ;

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन के बाद अभिदाता के लेखे में जमा की गई सभी राशियों पर जमा करने की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक के लिए ब्याज ;

(4) ब्याज की कुल रकम निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे और इससे अधिक को अलग एक रुपया गिना जाएगा) ।

परन्तु जब किसी अभिदाता के खाते में जमा रकम देय हो जाती है तो इस नियम के अधीन ब्याज, यथास्थिति केवल चालू वर्ष के आरंभ से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक जिसकी अभिदाता के लेखे में जमा रकम देय हो जाए, जमा किया जाएगा ।

(3) इस नियम में परिलब्धियों में से वसूली के मामले में जमा की तारीख उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें उसकी वसूली की जाती है और अभिदाता द्वारा भेजी जाने वाली रकम के मामले में उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें अभिदान प्राप्त किया गया है, यदि वह उस मास के पांचवें दिन के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि वह मास के पांचवें दिन या उसके पश्चात् प्राप्त होता है तो ठीक अगले मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ;

परन्तु जहां अभिदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और भत्ते लेने में विलम्ब हुआ है और परिणामस्वरूप निधि के संबंध में उसके अभिदान की वसूली में भी विलम्ब हुआ है वहां ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन नियमों के अधीन देय था भले ही वह वस्तुतः किसी भी मास में क्यों न लिया गया हो ;

परन्तु यह और कि नियम-12 के उपनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई रकम के मामले में, यदि वह मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाती है तो जमा करने की तारीख मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ;

परन्तु यह भी कि जहां मास की परिलब्धियां उसी मास के अन्तिम कार्यदिवस को ली और संघटित की जाती हैं, वहां अभिदाता के अभिदान की वसूली के मामले में जमा की तारीख आगामी मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ।

(4) नियम-20, 21 या 22 के अधीन संदन क जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उक्त मास के जिसमें संदन किए जाएं, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक या जिस मास में रकम देय हुई हो उसके पश्चात् छठे मास

के अन्त तक, इन दोनों अवधियों में से भी कम हो, उस व्यक्ति को देय होगी जिसे ऐसी रकम अदा की जानी है ;

परन्तु जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को कोई ऐसी तारीख सूचित कर दी है जिस तारीख को वह नकद अदायगी करने के लिए तैयार है अथवा अदायगी के लिए उस व्यक्ति को चैक भेज दिया है तो यथास्थिति ब्याज इस प्रकार सूचित तारीख या चैक भेजने की तारीख के पूर्ववर्ती मास के अन्त तक ही देय होगा ;

परन्तु यह और कि जहां अभिदाता सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्त को किसी पूर्व प्रभावी तारीख से ऐसे निगमित निकाय या संगठन में आमेलित कर लिया जाता है तो अभिदाता की निधि में संचतों पर देय ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए आमेलन की बाबत आदेश जारी किए जाने की तारीख वह तारीख समझी जाएगी जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो गई हो, बशर्ते कि आमेलन की तारीख से आरंभ होने वाली और आमेलन के आदेश जारी किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अभिदान के रूप में वसूल की गई रकम इस उप नियम के अधीन केवल ब्याज दिए जाने के प्रयोजन के लिए निधि में अभिदान समझी जाएगी ।

(5) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को सूचित कर देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा किन्तु यदि वह बाद में ब्याज मांगता है तो उस वर्ष के प्रथम दिन से जिसमें वह ब्याज की मांग करता है ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा ।

(6) ऐसी रकमों पर जो नियम 12 के उपनियम (3), नियम 20 या नियम 21 के अधीन निधि में अभिदाता के जमा खाते में प्रतिस्थापित की जाती है, ब्याज की गणना ऐसी दरों से की जाएगी जो नियम के उप नियम (ड) के अधीन उत्तरोत्तर विहित की जाए और जहां तक हो सके ऐसी रीति से जो इस नियम में विहित है ।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने निकासी की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निधि से निकाली है तो अधिक निकाली गई राशि, इस बात का ध्यान किए बिना कि अधिक निकाली गई राशि अग्रिम है या निकासी है या निधि से अन्तिम संदाय है, ब्याज सहित उसके द्वारा इसकी एकमुश्त अदायगी की जाएगी या राशि लौटाने में असफल होने पर अभिदाना की परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश जारी किया जाएगा । यदि वसूल की जाने वाली राशि अभिदाता की कुल मासिक परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली, ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि वसूली होने तक की उसकी परिलब्धियों के ब्रह्मश की मासिक गणितों में की जाएगी । इस उपनियम के लिए अधिक निकाली गई राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन अनिवार्य

प्रविष्ट निधि पर व्याज दर के $2\frac{1}{2}\%$ परिलिखित होगी। अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया गया व्याज "049—व्याज प्राप्तियां निगम की अन्य व्याज प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियां जीर्ण के अन्तर्गत, प्रविष्ट निधि से निकाली गई राशि पर व्याज उम जीर्ण के अधीन निगम के खाने में जमा किया जाएगा।

14. निधि से अग्रिम :—

(1) महानिदेशक या इस संबंध में उन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए ऐसी राशि के अग्रिम की अदायगी की अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विहित रूप में मंजूरी दे सकता है जो पूर्ण रूपों में होगी और अभिदाता के तीन मास के वेतन की रकम से या निधि में उसके नाम जमा रकम के आधे से, दोनों में से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी अर्थात् :—

(क) अभिदाता उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवास्था या निःशक्तता की बाबत व्यय का जिम्मे जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है अदायगी के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के खर्च की बाबत जिसमें जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय भी शामिल है निम्नलिखित दशाओं में पूरा करने के लिए अर्थात् :—

(1) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से ऊपर किसी शैक्षिक तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और

(2) भारत में हाई स्कूल स्तर के ऊपर के किसी शिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए परन्तु यह तब जबकि पाठ्यक्रम तीन वर्ष की कालावधि से कम न हो।

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुसार समुचित स्तर के किसी अनिवार्य व्यय के संदाय के लिए जो व्यय अभिदाता की रुढ़िगत प्रथा के कारण उसके सगाई या विवाह अन्वेषित या अन्य संस्कारों के संबंध में व्यय करना पड़े।

(घ) अभिदाता उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के खर्च वहन के लिए इस मामले में अग्रिम किसी अन्य सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए प्राप्त किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा।

(ङ) जहां अभिदाता अपने विरुद्ध किसी अभिकथित शासकीय कदाचार की बाबत जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है वहां उसकी प्रतिरक्षा का व्यय वहन करने के लिए।

(च) अपने निवास के लिए भूखंड या गृह या प्लॉट के निर्माण की लागत वहन करने के लिए या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा किसी गृह

नियंत्रण सचकारी कोटाहसी द्वारा भूखण्ड या प्लॉट के आवंटन को कोई अदायगी करने के लिए।

(2) महानिदेशक विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता को उपनियम (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है।

(3) किसी अभिदाता को उपनियम (1) में अभिकथित सीमा से अधिक अग्रिम या जब तक कि किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त की अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक कोई अग्रिम विशेष कारणों से ही जो लेखबद्ध किए जाएंगे मंजूर किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(4) जब उप नियम (3) के अधीन कोई अग्रिम किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त की अदायगी होने से पहले मंजूर कर दिया जाता है तो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किए गए अतिशेषों को इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्तें ऐसी समेधित रकम के संदर्भ में निश्चित की जाएंगी।

(5) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात् रकम ऐसे मामलों में जिम्मे ग्रन्थिम संदाय के लिए आवेदन नियम-25 के उपनियम (3) के खंड (2) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया हो, लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही की जाएगी।

टिप्पणी :—1

इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन में जहां स्वीकार्य हो महंगाई वेतन भी आता है।

टिप्पणी :—2

अभिदाता को नियम-14 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अग्रिम लेने की अनुमति प्रत्येक छह मास में एक बार दी जाएगी।

15. अग्रिम की वसूली :—

(1) अभिदाता से अग्रिम की वसूली उतनी समान मासिक किश्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी निर्दिष्ट करे किन्तु किश्तों की संख्या 12 से कम तब तक नहीं होगी जब तक अभिदाता स्वयं ऐसा विकल्प न दे और किसी भी दशा में 24 से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहां अग्रिम की रकम, नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, वहां मंजूरी प्राधिकारी 24 से अधिक किश्तें नियत कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में 36 से अधिक किश्तें नियत नहीं कर सकता है। अभिदाता अपनी इच्छानुसार किसी मास में एक से अधिक किश्तों का प्रतिमंदाय कर सकता है। प्रत्येक किश्त पूर्ण रूपों में होनी चाहिए और ऐसी किश्तें नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को यदि आवश्यक हो बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(2) वसूली नियम-12 में परिभाषित रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम दिया जाता है उसके ठीक बाद वाले मास के वेतन में आरंभ होगी। जब अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है या किसी कैलेंडर मास में दस या अधिक दिन के लिए ऐसी छुट्टी पर है जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता अथवा अर्द्धवेतन या अर्द्ध ओसत वेतन के समतुल्य या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता है तब उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। अभिदाता के लिखित निवेदन पर मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान वसूलियों को स्थापित कर सकता है।

(3) यदि अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर दिया गया है वह उसे ले जा चुका है तथा अग्रिम बाद में अदायगी पूरी होने से पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो ली गई कुल रकम या उसका अतिशेष का अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त भुगतान कर दिया जाएगा अथवा व्यक्तिगत की दशा में लेखा अधिकारी द्वारा निविष्ट किए जाने पर अभिदाता की परिनिबन्धियों में से लेखा अधिकारी के निर्देशानुसार एकमुश्त अथवा उसनी मासिक किस्तों में जो बारह से अधिक न हो कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा।

परन्तु ऐसा अग्रिम नामंजूर करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा कि अदायगी लागू क्यों न की जाए और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर भेज दिया जाता है तो इसे निर्णय के लिए महानिदेशक को भेजा जाएगा और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा है तो अग्रिम की वसूली उप नियम में विहित रीति से लागू की जाएगी।

(4) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां अभिदाता के खाने में जमा कर दी जाएंगी।

16. अग्रिम का सदोष उपयोग :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरी प्राधिकारी के लिए यह संदेह करने का कारण हो कि नियम 14 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए ऐसे धन का लिया जाना मंजूर किया गया था तो वह अभिदाता को अपने संदेह का कारण सूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करें कि क्या अग्रिम का प्रयोग उम्मी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए धन का लिया जाना मंजूर किया गया था। यदि पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण से मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को संबंधित रकम निधि में तत्काल अदा करने के लिए निर्देश देगा या व्यक्तिगत की दशा में अभिदाता की परिनिबन्धियों में से बाह्य

वह छुट्टी पर ही क्यों न हो, उसकी एक मुश्त कटौती करने का आदेश दिया जाएगा। परन्तु अदायगी की कुल रकम अभिदाता की परिनिबन्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिनिबन्धियों के अर्द्धांश की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा सम्पूर्ण रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती है।

टिप्पणी—इस नियम में परिनिबन्धियां शब्द में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है।

17. निधि से आहरण

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उन प्राधिकारियों द्वारा जो नियम 14 के उप नियम (2) के अधीन किसी भी समय विशेष कारणों के लिये नियमानुसार अग्रिम मंजूर करने में सक्षम है, अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विहित रूप में अभिदाता को रकम निकालने की मंजूरी दी जा सकती है। अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) पूरी होने के पश्चात् यह अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिये आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:—

(क) अभिदाता या अभिदाता की किसी सन्तान की उच्चतर शिक्षा का खर्चा, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, निम्नलिखित मामलों में वहन करने के लिये अर्थात्:—

(i) भारत में बाहर हाई स्कूल से ऊपर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिका या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, और

(ii) भारत में हाई स्कूल स्तर से ऊपर चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी अथवा विनिष्ट पाठ्यक्रम के लिये।

(ख) अभिदाता या उसके पुत्र या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार की सगाई/विवाह से संबंधित व्यय वहन करने के लिये;

(ग) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, वहन करने के लिये;

(2) अभिदाता की 10 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिये आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:—

- (i) अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह का निर्माण करना या उसे अर्जित करना या निर्मित फ्लैट अर्जित करना जिसमें स्थल की लागत भी सम्मिलित है;
- (ii) अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह निर्माण या उसे अर्जित करने अथवा निर्मित फ्लैट अर्जित करने के लिये स्पष्ट रूप से लिये गए उधार के कारण बकाया रकम की अदायगी करना;
- (iii) किसी गृहस्थल का अपने निवास के लिये उस पर गृह निर्माण के लिये खरीद करना या इस प्रयोजन के लिये स्पष्ट रूप से लिये गये उधार के कारण बकाया रकम की अदायगी करना;
- (iv) पहले से ही अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित गृह अथवा फ्लैट का पुनर्निर्माण करना या उसमें वृद्धि अथवा परिवर्तन करना;
- (v) इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह या इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर सरकार से लिये गए ऋण की सहायता से निर्मित गृह का नवीकरण, उसमें वृद्धि या परिवर्तन करना या उसे ठीक-ठाक रखना;
- (vi) खण्ड (iii) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह का निर्माण करना;
- (vii) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर निधि में उसके नाम जमा रकम से कृषि या कारखाने परिसर या दोनों को अर्जित करने के प्रयोजन के लिये दी जा सकती है;
- (viii) वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष के अभिदान के बराबर राशि एक बार अभिदाता द्वारा स्वयं चित पोषित तथा अंशदायी आधार पर निगम कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिये संदल की जायेगी।

टिप्पणी :—

वह अभिदाता जिसने गृह निर्माण के प्रयोजनों के अधिम मंजूर करने के लिए गृहनी विकास मंत्रालय की योजना के अधीन अधिम का लाभ उठाया है या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से सहायता दी गई है, उप नियम के खंड (i), (iii), (iv), और (vi) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और उपयुक्त योजना के अधीन लिये गये ऋण की अदायगी के प्रयोजनों के लिये भी, नियम 18 के उपनियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अंतिम रूप से रकम निकालने के मंजूरी का हकदार होगा।

यदि किसी अभिदाता के पास अपने इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिये गए ऋण की सहायता से गृह का निर्माण किया है तो वह अपने इयूटी के स्थान पर गृह स्थल खरीदने के लिये या दूसरे, गृह के निर्माण के लिये या निर्मित फ्लैट अर्जित करने के लिये

उप नियम (2) के खंड (i), (iii), और (iv) के अधीन अंतिम रूप से रकम निकालने के मंजूरी के लिये हकदार होगा।

टिप्पणी 2:—उप नियम (2) के खंड (i), (iii), (iv) या (vi) के अधीन रकम का निकाला जाना अभिदाता द्वारा निर्मित किये जाने वाले गृह या या की जाने वाली वृद्धि अथवा लिये जाने वाले परिवर्तनों या उस क्षेत्र के जहां स्थल या गृह स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् ही मंजूर किया जायेगा और केवल उसी मामलों में मंजूर किया जायेगा जिनमें रेखाचित्र वास्तव में अनुमोदित कराया जाता है।

टिप्पणी 3:—उप नियम (2) के खंड (ii) के अधीन मंजूर की गई आहरण की रकम, खंड (1) के अधीन पिछले आहरण की रकम सहित, उसमें से पिछले आहरण की रकम को घटाकर आवेदन की तारीख को बकाया तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिस मूल का पालन किया जाता है वह यह है :—[उस तारीख को बकाया तथा संबंधित गृह के लिये पिछले आहरण (आहरणों) की रकम से तीन चौथाई से पिछले आहरण (आहरणों) की रकम को घटा दे]।

टिप्पणी 4:—उप नियम (2) के खंड (i) या (iv) के अधीन रकम निकालने की अनुमति वहां भी दी जायेगी जहां गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम पर है परन्तु यह तब जबकि वह अभिदाता द्वारा किये गये नाम निर्देशन में भविष्य निधि में धन प्राप्ति करने के लिये प्रथम नाम निर्देशिनी हो।

टिप्पणी 5:—इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक बार रकम निकालने की अनुमति दी जायेगी किन्तु विभिन्न संतान के विवाह या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर बीमारियों या उस क्षेत्र के, जहां गृह या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा मम्यक रूप से अनुमोदित नये रेखाचित्र के अन्तर्गत आने वाले गृह या फ्लैट में अतिरिक्त वृद्धि या परिवर्तन को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। । किसी गृह को पूरा करने के लिये उप नियम (2) के खंड (i) या (vi) के अधीन दूसरा या उसके बाद रकम निकालने की अनुमति टिप्पण 3 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी 6:—यदि उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय पर नियम 14 के अधीन अधिम मंजूर किया जा रहा है तो इस नियम के अधीन रकम निकालने की मंजूरी नहीं दी जायेगी।

(3) रकम निकालने की मंजूरी देने के पश्चात् ऐसे मामलों में, जिनमें अंतिम भुगतान के लिये आवेदन नियम 25 के उप नियम (3) के खंड (ii) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया था, रकम लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर ली जायेगी।

18. रकम निकालने की शर्तें:

- (1) अभिदाता द्वारा निधि में अपने खाते में जम रकम से नियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक

प्रयोजनों के लिये, एक समय पर निकाली गई कोई राशि सामान्यतया ऐसी रकम के आधे या छह मास के बतन, दोनों में से जो कम हो, अधिक नहीं होगी। परन्तु मंजूरी प्राधिकारी इस सीमा से अधिक रकम का निकालना, जो निधि में उसके खाते में जमा अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, (1) उस उद्देश्य को, जिसके लिये रकम निकाली जा रही है, (2) अभिदाता की हैसियत को और (3) निधि में उसके खाते में जमा रकम को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए मंजूर कर सकता है।

परन्तु नियम 17 के (घ) के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये निकाली जाने वाली अधिकतम रकम गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिये शहरी विकास मंत्रालय की योजना के नियम 2(क) और 3(ख) के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि किसी अभिदाता के मामलों में जिसने गृह निर्माण प्रयोजनों की बाबत अग्रिम के अनुदान के लिये शहरी विकास मंत्रालय की योजना के अधीन कोई अग्रिम लिया है या किसी जिसे अन्य सरकारी स्रोत से इस बगरे में कोई सहायता दी गई है, इस उप-नियम के अधीन निकाली गई राशि और उपर्युक्त योजना के अधीन दिये गये अग्रिम या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की राशि मिलकर उपर्युक्त योजना के नियम 2(क) और 3(ख) के अधीन समय-समय पर विहित की गई अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1:—नियम 17 के उप नियम (2) के खंड (1) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई आहरण की राशि किशतों में निकाली जा सकती है और किशतों की संख्या मंजूरी की तारीख से बारह महीने के कैलेण्डर की अवधि में चार से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2:—उन मामलों में जिनमें अभिदाता को खरीदे गए स्थल या गृह अथवा फ्लैट या दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिये भुगतान किशतों में करना है, उसे तब-तब रकम निकालने की अनुमति दी जायेगी जब जब उससे ऐसी किशतों का भुगतान करने के लिये कटौत जायेगा। ऐसा प्रत्येक भुगतान नियम 16 के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान माना जायेगा।

(2) वह अभिदाता जिसे नियम 17 के अधीन निधि में से धन निकालने की अनुमति दी गई है, मंजूरी प्राधिकारी का ऐसे यथाचित समय के भीतर जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में चूक जाता है तो इस प्रकार निकाली गई कुल राशि अथवा उसके उतने भाग को जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह निकाला गया था,

उपयोग में नहीं लाया गया है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में एकमुश्त लौटाया जाएगा और ऐसा भुगतान करने में चूक होने की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी उस रकम को उसकी परिनिधिधियों से या तो एकमुश्त या उसकी मासिक किशतों में, जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए, वसूल करने का आदेश देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन आहरण को धन वापसी लागू करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा कि अदायगी को लागू क्यों न किया जाए और यदि मंजूरी प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी इस उप-नियम के अधीन विहित रीति से अदायगी करवाएगा।

3(क) वह अभिदाता जिसे नियम 17 के उप नियम (2) के खंड (1), खंड (i) और (iii) के अधीन निधि में अपने नाम जमा रकम निकालने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से निर्मित या अर्जित गृह या खरीदे गए गृह स्थल का कब्जा विक्रय बंधक (महानिदेशक के नाम में बंधक से भिन्न) दान या विनिमय द्वारा अथवा किसी रूप में, महानिदेशक को पूर्व अनुमति के बिना नहीं देगा।

परन्तु ऐसी अनुमति किसी ऐसी अवधि के लिए गृह या गृह स्थल को पट्टे पर देने के लिए

(1) जो तीन वर्ष से अधिक न हो, या

(2) उसे किसी आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में जिसने नये गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में वृद्धि या परिवर्तन के लिए कोई ऋण देता हो, बंधक रखने के लिए आवश्यक नहीं होगी।

(ख) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, कि, यथास्थिति, गृह या गृह स्थल उसके कब्जे में ही है अथवा वह पूर्वोक्त के अनुसार बंधक रख दिया गया है अथवा अस्थायी अंतरित कर दिया गया है या पट्टे पर दे दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वह मूल विक्रय बंधक या पट्टा विलेख तथा ऐसे अन्य दस्तावेज भी जिन पर सम्पत्ति पर उसका हक आधारित है, प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी समय अभिदाता महानिदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना गृह या गृह स्थल का कब्जा त्याग देता है तो वह तुरन्त अपने द्वारा निकाली गई राशि का निधि में एकमुश्त भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान करने में चूक की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी, अभिदाता को इस विषय में अस्थावेदन करने का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् उक्त राशि को अभिदाता की परिनिधिधियों में से या तो एकमुश्त अथवा उसकी मासिक किशतों में जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, वसूल करवाएगा।

टिप्पणी : उस अभिदाता से जिसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से ऋण लिया है और उसके बदले में गृह या गृह स्थल निगम को बंधक रख दिया है, निम्नलिखित आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—

घोषणा

“मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस गृह या गृह स्थल के निर्माण के लिए या अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से धन निकाला था वह मेरे कब्जे में ही है किन्तु निगम के पास बंधक रख दिया गया है।”

19. अग्रिम का “आहरण” में परिवर्तन :

वह अभिदाता जिसने नियम 14 के अधीन उक्त नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया है अथवा भविष्य में ले सकता है, नियम 17 और 18 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर देने पर स्वविवेकानुसार और मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को संबंधित लिखित निवेदन करके अग्रिम के बकाया अतिशेष को अन्तिम आहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पण 1 : प्रशासनिक अधिकारी अराजपत्रित अभिदानाओं के मामले में कार्यालय के प्रधान से और राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में संबंधित खजाना अधिकारी को वेतन बिलों में से वसूलियाँ रोकने के लिए तब कह सकता है जब ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसे प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को भेज दिया जाता है प्रशासनिक प्राधिकारी अभिदाता का सूचना भेजने वाले पत्र की एक प्रति उस खजाना अधिकारी को भेजेगा जिससे वह अभिदाता अपना वेतन प्राप्त करता है ताकि आगे वसूलियाँ रोकने की अनुमति दी जा सके।

टिप्पण 2 : नियम 18 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, परिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा रकम या अभिदान तथा उस पर व्याज और अग्रिम की बकाया रकम को अतिशेष माना जाएगा। प्रत्येक रकम का निकायना पृथक रकम का निकायना माना जाएगा और एक से परिवर्तनों की स्थिति में वही सिद्धांत लागू होगा।

20. निधि में से संचयों का अन्तिम रूप से आहरण :

जब अभिदाता सेवा छोड़ दे तब निधि में उसके नाम जमा रकम उसे देय हो जाएगी :

परन्तु वह अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में सेवा में बहाल कर दिया गया है यदि महानिदेशक ऐसा करने की अपेक्षा करें तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि में से उसे भुगतान की गई रकम का नियम 13 के उपबन्धित दर से व्याज के साथ, नियम 21 के परन्तुक में विहित रीति से भुगतान करेगा। उस प्रकार भुगतान की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 :—सविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से अथवा उस अभिदाता से, जो सेवा में नियुक्त हो गया है, जिसे बाद में सेवा के व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित

किया गया है, भिन्न अभिदाता के बारे में उस दशा में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है। जब उसे सेवा में व्यवधान बिना राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे किसी दूसरे विभाग के अधीन (जिसमें वह किन्हीं अन्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होता है) किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसका अपने पूर्व पद से कोई संबंध नहीं रह जाता। ऐसे मामले में उससे अभिदाय व्याज सहित :—

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में है तो अन्य निधि में उसे निधि के नियमों के अनुसार अंतरित कर दिए जाएंगे, या

(ख) यदि नया पद किसी राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिदानों और व्याज के ऐसे अंतरण के लिए सहमति दे देती है तो संबंधित राज्य सरकार के अधीन नये लेखों में अंतरित कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी :—स्थानांतरण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की समुचित आशा से कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पद त्याग के मामले आएंगे। ऐसे मामलों में जिस सेवा में व्यवधान हो जाता है उनमें व्यवधान केवल भिन्न स्थानांतरण के लिए दी गई पदग्रहण अवधि तक सीमित होगा।

यही उपबंध ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें छटनी पश्चात् तुरन्त उसी या भिन्न सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त हो जाता है।

स्पष्टीकरण 2 :—सविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से भिन्न अभिदाता, जो सेवा निवृत्त हो चुका है और जिस बाद में, सेवा में व्यवधान के बिना, किसी ऐसे निर्गमित निकाय, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में पुनः नियोजित अथवा स्थानांतरित किया जाता है, तो अभिदानों की रकम का उस पर व्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, अपितु वे उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन नये भविष्य निधि लेखों में अंतरित कर दी जाएगी।

स्थानांतरण के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निर्गमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की यथोचित अनुमति से पदग्रहण करने के लिए सेवा में पदत्याग के मामले भी आते हैं। नये पद का भार ग्रहण करने में लगने वाले समय को, याद वह समय सरकारी कर्मचारी की एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए स्वीकार्य पद ग्रहण अवधि से अधिक नहीं है तो, सेवा भंग नहीं माना जाएगा।

परन्तु किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले अभिदाता के अभिदान की रकम और उस पर व्याज यदि अभिदाता ऐसा चाहता है और यदि संबंधित उद्यम ऐसे अंतरण के लिए सहमत हो जाता है तो, ऐसे उद्यम के अधीन उसके नये भविष्य निधि लेखों को अंतरित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अभिदाता ऐसे अंतरण की इच्छा नहीं करता है या संबंधित उद्यम की कोई भविष्य निधि नहीं है तो उपरोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

21. अभिदाता की सेवानिवृत्ति :

जब

(क) अभिदाता सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह किसी अवकाश विभाग में नियोजित है तो जब वह अवकाश के साथ सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है, या

(ख) अभिदाता को छुट्टी पर रहने के दौरान सेवा निवृत्ति होने की अनुमति दे दी गई है या निःसश्रम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे और सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब निधि में उसके नाम जमा रकम, उसके द्वारा इस निमित्त लेखा अधिकारी को आवेदन किए जाने पर अभिदाता को सौंप दी जाएगी :

परन्तु यदि अभिदाता छुट्टी पर वापस आ जाता है तो महानिदेशक द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई रकम का उस पर नियम 13 में उपबंधित दर से व्याज के साथ नकद या प्रतिभूतियों के रूप में किण्वों में या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से यसूली द्वारा उस अधिकारी के निदेशानुसार जो ऐसे अग्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम है और जिसकी मंजूरी देने के लिए नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है अपने खाते में जमा कर किए जाने के लिए निधि में भुगतान करेगा।

22. अभिदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया :

निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के देय हो जाने से पूर्व या जहां रकम देय हो गई है वहां भुगतान किए जाने के पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर :

(1) जहां अभिदाता कुटुम्ब छोड़ जाता है:—

(क) यदि नियम 2 के उपबंधों के अनुसरण में अथवा इसके पूर्व तत्समान किसी नियम के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया नामनिर्देशन कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में है तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका कोई भाग जिसके संबंध

में नामनिर्देशन किया गया है, अभिदाता के के नामनिर्देशनी या नामनिर्देशनियों के नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जाएगा,

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है अथवा यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के केवल कुछ भाग के संबंध में है तो, यथा स्थिति, संपूर्ण रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में कोई नामनिर्देशन वात्पयित है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों के बीच समान अंशों में से देय होगा।

परन्तु ऐसा कोई अंश

(1) उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(2) मृत पुत्र के उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(3) उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृत पुत्र की उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं, देय नहीं होगा;

(ग) यदि खंड (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कुटुम्ब का कोई सदस्य है।

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान को आपस में समान भागों में केवल वह अंश प्राप्त होगा जो उस पुत्र को यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता तथा प्रथम परल्लुके के खंड (1) के उपबंधों में छूट प्राप्त होती तो प्राप्त होता।

(2) यदि अभिदाता अपना कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है, तब यदि नियम 1 के उपबंधों या इसमें पूर्व प्रवृत्त तत्समान किसी नियम के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसके नामनिर्देशन संबंधित है अभिदाता के नामनिर्देशनी या नामनिर्देशनियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जाएगा।

23. जमा राशि—भारत वीमा योजना—

30 सितम्बर, 1991 को या उससे पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर नया जिसपर नियम 24 लागू नहीं होता है अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में अंशित अतिशेष के बराबर अनिवार्य रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के मास पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम हो—

(1) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया जिसका परिशोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 1300 या उससे अधिक है— 4000 रु.

(2) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिशोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 900 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 1300 रुपये से कम है— 2500 रुपये

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिशोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 291 रुपए या उससे अधिक है किन्तु 900 रुपये से कम है— 1500 रुपये।

(4) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिशोधन पूर्व वेतनमान का वेतन 291 रुपए से कम है— 1000 रुपए।

(ख) इस नियम के अधीन देय अनिवार्य रकम दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी—1

अंशित अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है पूर्व 36 मास से से प्रत्येक मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इन प्रयोजनों के लिए और ऊपर

विहित न्यूनतम अतिशेष की आवश्यकता नहीं है—

(क) मार्च के अंत के अतिशेष में नियम 13 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक व्याज भी सम्मिलित होगा,

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अंतिम मास मार्च नहीं होता, उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में उस वितीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत व्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी—2

इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपों में होता चाहिए। यदि किसी देय रकम में रुपये का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपये में पूर्ण-कृत कर दिया जाना चाहिए। पचास पैसे की गणना एक और रुपए के रूप में की जाएगी।

टिप्पणी—3

इस योजना के अधीन देय धनराशि वीमा धन के किस्म की है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी—4

यह योजना निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को म्यशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानान्तरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानान्तरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी—5

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या नियम 27 के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया है, किन्तु जिसकी मृत्यु यथास्थिति निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदानों की रकम और नियोजक का अभिदान, यदि कोई हो, व्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवश्यक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई भेदा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पणी-6

इस योजना की वाबन व्यय के बजट प्राक्कलन निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के लेखा को ध्यान में रखते हुए उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

24. जमा राशि-सहबद्ध बीमा परिशोधित योजना :—

अभिदाता की मृत्यु पर अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम न हो —

(1) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपयुक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 4000 रुपये या उससे अधिक है—12,000 रुपये;

(2) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपयुक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 2900 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 4000 रुपये से कम है—7500 रुपये;

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपयुक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,151 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 2,900 रुपये से कम है—4500 रुपये।

(4) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपयुक्त अवधि के अधिकांश भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1151 रुपये से कम है—3000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी—1 औसत अतिशेष की गणना उस मास में, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में ने प्रत्येक मास के अन्त में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए थी—

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम 13 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक व्याज भी सम्मिलित होगा;

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अन्तिम मास मार्च नहीं है, तो उक्त अन्तिम मास के अन्त के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की अवधि की वास्तव व्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी—2 इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपों में होगा। यदि किसी देय रकम में रुपये का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। पचास पैसे की गणना एक रुपये के रूप में की जाएगी।

टिप्पणी—3 इस योजना के अधीन देय धन-राशि बीमा धन के किस्म की है और इसलिए अविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस योजना के अधीन देय धन-राशि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी—4 यह योजना निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी—5(क): ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या नियम 27 के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया है, किन्तु, जिसकी मृत्यु, यथा स्थिति निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी वास्तव उसके अभिदानों की रकम और नियोजक का अभिदान, यदि कोई हो, व्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खंड (क) और (ग) के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी है।

टिप्पण 6:—इस गोशना की श्रावण वय के वज्र प्राक्कलन निधि के लेखा को प्रनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के रख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवा निवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

25. निधि में रकम की अदायगी की रीति :—

(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो जानी है तो लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि यह उपनियम (3) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी अदायगी करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी मंदन समनुदेशित, या परिदत्त की जानी है, पागल है और सम्पदा के लिए पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो ऐसी अदायगी या पुनः समनुदेशन या परिदाम ऐसे प्रबन्धक को किया जाएगा, उम पागल को नहीं।

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसे राशि देय है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो अदायगी पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार क्लबटर के आदेश से उस व्यक्ति को की जाएगी जिसकी देख-रेख में ऐसा पागल व्यक्ति है और लेखा अधिकारी केवल उतनी रकम उसे भुगतान करेगा जो वह उस व्यक्ति को जिसकी देख-रेख में ऐसा पागलपन है, देना ठीक समझे तथा अतिशेष, यदि कोई हो अथवा उसका उतना भाग, जितना लेखा अधिकारी ठीक समझे, ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भरण-पोषण के लिए आश्रित हैं।

(3) निकाली गई रकम का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकम देय है उन्हें रकम को भारत में प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। अभिदाता द्वारा भुगतान का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी अर्थात् :—

(1) अभिदाता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्रारूप (फार्म) या तो उसकी अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या यदि उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख

पूर्वतर हो तो उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि उन प्रारूपों को सम्पक रूप से पूरा करने के पश्चात् अभिदाता प्रारूप प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वापस कर दे। अभिदाता अपने कार्यालय या विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी के समक्ष निधि की रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आवेदन :—

(क) निधि में उसके नाम जमा उतनी रकम के लिए किया जाएगा जितनी उसकी अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख है अथवा सेवा निवृत्ति का प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा विवरण में उपदर्शित किया गया हो, अथवा

(ख) यदि अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तो उतनी रकम के लिए किया जाएगा तो खाना वही में उपदर्शित है।

(ii) कार्यालय अथवा विभाग का प्रधान आवेदन को, लिए गए अग्रिमों और नाम उन अग्रिमों के कारण जो अभी चालू हों, की गई वसूलियों तथा प्रत्येक अग्रिम के संबंध में वसूल की जाने वाली किश्तों की संख्या उपदर्शित करने हुए लेखा अधिकारी को भेजेगा और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी गई अभिदाता के पिछले लेखा विवरण में सम्मिलित अवधि के पश्चात् की गई रकम की निकालियां भी प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) लेखा अधिकारी खाता वही से सत्यापन करने के पश्चात् अधिवापित की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व किन्तु अधिवर्षिता की तारीख पर देय उस रकम का प्राधिकार जारी करेगा जो आवेदन में उपदर्शित की गई है।

(iv) खंड (iii) में उल्लिखित प्राधिकारी भुगतान की प्रथम किश्त होगी। भुगतान के लिए विशेष प्राधिकारी अधिवर्षिता के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। उसका संबंध उस अभिदाता से होगा जो अभिदाता

द्वारा खंड (i) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन में उल्लिखित रकम के पश्चात् किया जाए और इसमें प्रथम आवेदन के समय चालू अग्रिमों के प्रति किश्तों का संग्रह भी होगा।

- (v) अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात् अग्रिम रकम का निकालना मंजूर किया जा सकता है, किन्तु अग्रिम/रकम निकामी की रकम संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर ली जाएगी और लेखा अधिकारी इसकी व्यवस्था मंजूरी प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी उसे प्राप्त होने पर यथाशीघ्र करेगा।

टिप्पण :—जब नियम 20, 21 और 22 के अधीन अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो जाए तो लेखा अधिकारी उपनियम (3) में उपदर्शित रीति में रकम के तत्परता से भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा।

26. सरकारी कर्मचारी के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

(क) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की किसी अन्य अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है, केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में पेंशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से शासित होता है तो स्थानांतरण की तारीख को ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा अभिदानों की रकम, उस पर व्याज सहित, निधि में उसके जमा खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

परन्तु जहां अभिदाता किसी राज्य सरकारी की अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था वहां उस सरकार की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(ख) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो राज्य रेल भविष्य निधि या केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य अभिदायी भविष्य निधि या राज्य अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है, केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में पेंशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से शासित होता है और जहां तक अभिदाता ऐसी निधि के नियमों से शासित होते रहने का चयन नहीं करता है, जबकि ऐसा विकल्प दिया गया है :—

- (1) स्थानांतरण की तारीख को ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके नाम जमा अभिदानों की रकम, उस पर व्याज सहित अन्य सरकार की, यदि

कोई हो, तो उसकी सहमति से निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी;

- (2) ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में उसके नाम जमा सरकारी अभिदायों की रकम, उस पर व्याज सहित, अन्य सरकार की, यदि कोई हो, तो उसकी सहमति से केन्द्रीय राजस्व (सिविल) में जमा करा दी जाएगी;

- (3) अभिदाता स्थाई स्थानांतरण की तारीख से पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की गणना के संबंध में जहां तक सुसंगत पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय विस्तार है, पेंशन के लिए हकदार होगा।

टिप्पणी 1: इस नियम के उपबंध ऐसे अभिदाता पर लागू नहीं होते जो सेवानिवृत्त हो गया है और बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित किया गया है और उस अभिदाता पर लागू नहीं होता जिसकी पिछली नियुक्ति संविदा के आधार पर थी।

टिप्पणी 2: परन्तु इस नियम के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन्हें सेवा में व्यवधान के बिना चाहे अस्थायी रूप से या स्थाई रूप से, सेवा में त्यागपत्र के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है।

27. स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

किसी व्यक्ति को सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन से सरकारी सेवा में स्थानांतरित किए जाने पर प्रक्रिया—यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे निधि के फायदे दिए जाने लगे हैं, पहले सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी भविष्य निधि में अभिदाता था तो उसके अभिदानों और नियोजकों के अभिदायों की रकम, यदि कोई हो, उन पर व्याज सहित, ऐसे निकाय की सहमति से निधि में उसके लेखे में अंतरित कर दी जाएगी।

28. अग्रदायी भविष्य निधि (भारत) में रकम का स्थानांतरण :

यदि निधि के किसी अभिदाता को बाद में अभिदायी भविष्य निधि (भारत) के फायदे दिए जाने लगे हैं तो उसके अभिदानों की रकम, उस पर व्याज सहित, अभिदायी भविष्य निधि (भारत) में उसके जमा लेखे में अंतरित कर दी जाएगी।

टिप्पणी :—इस नियम के उपबंध उस अभिदाता पर लागू नहीं होंगे जो संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से निवृत्त हो गया है और जिसे बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना किसी अन्य पद

पर, जिसमें अभिदायी भविष्य निधि के फायदे प्राप्त होते हैं, पुनः नियोजित किया गया है।

29. स्पष्टिक मामलों में नियमों के उपबंधों में छूट :

यदि स्थाई समिति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के प्रवर्तन में अभिदाता को भारी कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो वह, इन नियमों में किसी बात के होने हुए भी, ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करने के पश्चात् ऐसे अभिदाता के मामले का निपटारा ऐसी रीति में करेगा जो उन्हें विधिपूर्ण और साम्यपूर्ण प्रतीत हो।

30. अभिदान के भुगतान के समय लेखा संख्या का उद्धृत किया जाना :—

भारत में अभिदान का भुगतान करने समय चाहे वह परिलब्धियों में से कटौती द्वारा हो या नकद हो अभिदाता निधि की लेखा संख्या सूचित करेगा जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी। संस्था में होने वाला परिवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा उन्हीं प्रकार अभिदान को सूचित किया जाएगा।

31. अभिदाता को वार्षिक लेखा विवरण दिया जाना :

(1) लेखा अधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को उसका आरम्भिक अनिवेश, वर्ष के दौरान जमा की गई या

नाशे वाली गई कुल रकम वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई व्यय की कुल रकम तथा उभ तारीख को अंतिम अनिवेश उपदर्शित किया जाएगा। लेखा अधिकारी, लेखा विवरण के समय यह पुष्टताएँ संलग्न करेगा कि क्या :

(क) अभिदाता नियम 7 या इससे पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) उन मामलों में जिनमें अभिदाता के नियम 7 के उप नियम (1) के परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, क्या अभिदाता को कोई कुटुम्ब हो गया है।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण का शुद्धता के संबंध में अपना समाधान कर लेना चाहिए और त्रुटियाँ विवरण प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को सूचित कर दी जानी चाहिए।

(3) यदि अभिदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो लेखा अधिकारी वर्ष में एक बार किन्तु एक से अधिक बार नहीं अभिदाता को उक्त अन्तिम मास की समाप्ति पर जिसकी बाबत लेखा लिखा जा चुका है, निधि में उसके नाम जमा कुल रकम सूचित करेगा।

32. निर्वचन :

यदि उन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न है तो वह केन्द्रीय सरकार, आम मंत्रालय का निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका निर्णय करेगा।

अनुसूची-1 [नियम 7(3) देखें]

नामांकन प्रारूप

लेखा संख्या

मे नीचे उल्लिखित निधि में मेरे नाम जमा रकम के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी स्थिति में जब वह देय हो चुकी हो, किन्तु उसकी अदायगी न हुई हो मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति (अश्वितियों) को, नियम 2 में क्या परिभाषित मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं/मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य नहीं है/हैं, नामित करता हूँ।

नामांकन प्रारूप

(नियम-2)

नामिनी (नामिनियों)	अभिदाता के साथ नातेदारी	नामिनी (नामिनियों)	प्रत्येक ऐसी नामिनी को देय भाग	आकस्मिकताएँ जिसके होने पर नामांकन अधिविधि मान्य हो जाएगी	ऐसा/ऐसे व्यक्ति (अश्वितियों), यदि कोई हो/ हो के नाम पता/पते और नातेदारी जिसको/जिनको नामिनी का अधिकारी उस स्थिति में मिल जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	जैसा कि नियम 2 में परिभाषित है उसके अनुसार यदि नामिनी कुटुम्ब का सदस्य नहीं है तो कारण बताएँ
-----------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
तारीख	19	को	स्थान पर				
दो माभियों के हस्ताक्षर, नाम तथा पते							
1.							
2.							

अभिदाता के हस्ताक्षर
 स्पष्ट अक्षरों में नाम
 पदनाम
 हस्ताक्षर
 1.
 2.

कार्यालय प्रधान/बेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा नामांकन, पदनाम
 नामांकन प्राप्त होने की तारीख

कार्यालय प्रधान/लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर
 पदनाम
 तारीख

अभिदाता के लिए अनुदेश :—

(क) अपना नाम लिखिए ।

(ख) निधि के नाम को उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए ।

(ग) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में दी गई कुटुम्ब की परिभाषा पुनः नीचे दी जाती है, परिवार से अभिप्रेत है :—

(1) पुरुष अभिदाता की दशा में पत्नी या पत्नियाँ, माता पिता, सन्तानें, अवयस्क भाई अविवाहित बहनें मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्तानों और जहाँ अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं वहाँ उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक् हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, रुढ़ी जन्य विधि के अधीन उससे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी की द्वाय में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में जाना जाता रहेगा यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है।

(2) स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता पिता, सन्तानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्तानों और जहाँ अभिदाता के माता पिता जीवित न हों वहाँ उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को उपाजित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति का तब से जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप से रद्द न कर दें यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

टिप्पणी :—सन्तान से धर्मज सन्तान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहाँ अभिदाता को शासित करने वाली स्त्रीय विधि द्वारा वत्सक को मान्यता प्राप्त है वत्सक सन्तान आती है।

(घ) कालम 4 यदि केवल एक ही व्यक्ति को नामित किया जाता है तो उस नामित की सामने "सम्पूर्ण" लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को देय भाग इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उनके अन्तर्गत आ जाए।

(ङ) कालम 5—इस कालम में नामित (नामितों) की मृत्यु की आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(च) कालम 6—अपना नाम न लिखें।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में एक रेखा खींच दें जिससे आपके हस्ताक्षर करने के बाद उस स्थान में कोई नाम न लिखा जा सके।

अनुसूची 2

[नियम 14(1) और 17(1) देखें]

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/राशि निकासी के लिए आवेदन पत्र

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या
3. पदनाम
4. (1) वेतन रुपये
- (2) मासिक अभिदान रुपये
5. निकासी के मामले में
- (1) जन्म तिथि
- (2) नियुक्ति की तारीख
- (3) सेवा निवृत्ति की तारीख

आवेदन की तारीख को अभिदाता के खाते में कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1. वर्ष 199..... के लेखा विवरण के अनुसार
रु..... अतिशेष है।
2. दिनांक..... से..... तक..... रुपये
मासिक अभिदान से कुल जमा राशि..... रुपये
3. अग्रिम राशि की वापसी.....
4. दिनांक..... से..... से..... तक की अवधि के दौरान निकासित रुपये
.....
5. के नाम बकाया निवल धन राशि रुपये.....
6. अग्रिम की बकाया राशि, यदि कोई है, तथा ली गई राशि का प्रयोजन.....
..... ली गई राशि रुपये..... आवेदन
की तारीख को..... शेष बकाया राशि रु.....
7. मांगे गए अग्रिम की राशि रुपये.....
8. क. किस प्रयोजन के लिए अग्रिम चाहिए.....

ख. नियम जिनके अन्तर्गत आवेदन अधिमान्य होता है.....

ग. यदि भवन निर्माण आदि के प्रयोजन के लिए अग्रिम मांगा जाता है तो निम्नलिखित सूचना दी जाए :—

- (1) प्लॉट स्थल तथा उसकी पैमाइश.....
- (2) क्या यह प्लॉट पूर्ण स्वामित्व में है अथवा पट्टे पर.....
- (3) निर्माण का नक्शा.....
- (4) यदि फ्लैट अथवा प्लॉट हाऊस बिल्डिंग समिति से खरीदा जा रहा है तो उस समिति का नाम.....
फ्लैट अथवा प्लॉट तथा उसकी पैमाइश आदि.....

(5) निर्माण की लागत.

(6) यदि प्लट दिव्या विकास प्राधिकरण अथवा किसी हाउसिंग बोर्ड ने खरीदा जाता है वा उसके स्थान, परिभाषा आदि का उल्लेख किया जाए.

(7) यदि अग्रिम संतान शिक्षण प्रयोजन के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए.

(1) पुत्र/पुत्री का नाम.

(2) कक्षा तथा संस्थान/कालेज जहां अध्ययन कर रहा/रही है.

(3) क्या वह दिवाछात्र है अथवा छात्रावास में रहता है.

(8) यदि अग्रिम परिवार के किसी रोगी के उपचार के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिए जाए:

(1) रोगी का नाम तथा उसके साथ संबंध.

(2) अस्पताल/औपचारिक/उम डॉक्टर का नाम जहां रोगी का उपचार चल रहा है.

(3) यदि बहिरंग अथवा अंतरंग रोगी है.

(4) क्या प्रतिभूति डालव्य है अथवा नहीं.

टिप्पणी.—8(ग) से 8(ङ) के अधीन मामलों में किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेजों माध्य की आवश्यकता नहीं होगी।

9. समर्थन अग्रिम की राशि (मद 6 और 7) तथा मासिक किस्तों का संख्या जिसमें गमेकित अग्रिम राशि मांगे का. किस्तों में वितरण का प्रस्ताव है।

10. अभिदाता का अतः पर्याप्त स्थितियों के पूर्ण व्यौर जिसमें अग्रिम के लिए आवेदन पत्र को उचित उद्देश्य प्राप्त हो सके।

में प्रमाणित करता है कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दिए गए व्यौर सही हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग

सहायक प्राधिकारी का अधिकार/टिप्पणी

हस्ताक्षर

पदनाम

[प्राद. सं. एस 65012/1/90-एसएस-1]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th September, 1995

G.S.R. 431.—Whereas certain draft rules namely the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1993 were published as required under sub-section (i) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. GSR 575 dated the 27th October, 1994 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 19th November, 1994 inviting objections or suggestions from any persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date of its publication in the official Gazette.

And whereas, the said draft Rules were published in the Official Gazette on the 19th November, 1994.

And whereas the Gazette copies of the draft rules in which they were published were made available to the public on 19th November, 1994.

And whereas, no objections or suggestions have been received from any person likely to be affected thereby.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the said Act, and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, except as respects things done or omitted

to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: (1) In these rules unless the context otherwise requires—

(a) "Accounts Officer" means the Financial Commissioner of the Employees' State Insurance Corporation or such other officer as may be specified in this behalf;

(b) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(c) "Corporation" means Employees' State Insurance Corporation.

(d) "Emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant if admissible and any remuneration of the nature of pay received in respect of deputation;

(e) "Employee" means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Corporation, other than persons on deputation;

(i) "Family" means—

- (1) In the case of a male-subscriber the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that he shall continue to be so regarded;

- (2) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Explanation—In this clause, child means legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber;

- (c) 'Fund' means the Employees State Insurance Corporation General Provident Fund;
- (d) 'Leave' means any kind of leave recognised by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 ;
- (e) 'Service' means service under the Corporation;
- (f) 'Year' means a financial year.

- (2) Any other expressions used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or Employees State Insurance Act, 1948 or in the Fundamental Rules, is used in the sense thereon defined but not defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) the Employees' State Insurance Corporation (Central) Rules, 1950, Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 or the Fundamental Rules, as the case may be.

- (3) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the General Provident Funds as heretofore existing or of constituting any new fund.

3. Constitution of the Fund—(1) The Fund shall be maintained in Rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited to a Fund called 'The Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund'. Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to the Deposit Account at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. Operation of Fund by the Accounts Officer—The Fund shall be operated upon by the Accounts Officer who is hereby authorised to arrange for all payments required to be made under these rules.

5. Investments.—All monies belonging to the Fund shall be invested in the manner specified in the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, for investment of monies belonging to the Employees' State Insurance Fund.

6. Conditions of eligibility—All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to CPF) and all permanent employees shall subscribe to the Fund :

Provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund while he retains his right to subscribe to such a Fund :

Provided further that such of the temporary employees who have completed continuous service of one year before the 31st March, 1960 shall not subscribe to the Fund from a date earlier than the 1st April, 1960.

Explanation—A temporary employee who completes one year of continuous service on any day of a month shall subscribe to the fund with effect from the subsequent month.

Note-1—Apprentices and Probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of this rule.

Note-2—A temporary employees who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

Note-3—Temporary employee (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of one year's service.

7. Nominations :—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid :

Provided that where a subscriber is a minor he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority :

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided also that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination in accordance with this rule.

If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1) he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees, in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Forms set forth in the Schedule I appended to these rules.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination made by him by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall alongwith such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provision of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

- (a) That in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon the specified nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nominations :

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has any other members in his family, be such member or members of the family :

Provided further that where the subscriber confers the right under this clause on more than one person, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

- (b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of his family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso there to the subscriber send a notice in writing to the Accounts Officer cancelling the nomination, together with the fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Note : In this rule, unless the context otherwise requires 'person' or 'persons' shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any Charitable or other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said Funds or Trust authorised to receive payments.

8. Subscriber's Account : An account shall be opened in the name of each subscriber to show—

- (i) his subscriptions;
- (ii) interest, as provided in rule 13 on subscriptions;
- (iii) advances and withdrawals from the Fund.

9. Conditions and rates of subscriptions : (1) A subscriber shall subscribe to the Fund every month except during the period when he is under suspension.

Provided that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrear of subscription payable in respect of the said period.

Provided further that subscriber may, at his option not subscribe during any period of leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

Note 1.—The holder of a seasonal post in an establishment need not subscribe to the Fund, during the period of his employment.

Note 2.—A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his option not to subscribe during leave referred to in the second proviso to sub-rule (1) in the following manner :—

- (a) If he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave.
- (b) If he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the head of office before he proceeds on leave. On failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an option to subscribe.

Note.—The option of a subscriber once intimated under this sub-rule shall be final.

(3) A subscriber who has under rule 17 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

10. Rates of subscription—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely—

- (a) It shall be expressed in whole rupees.
- (b) It may be any sum, so expressed which shall not be less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments :

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to the Employees' State Insurance Corporation Contributory Provident Fund at the higher rate of 8-1/3%, it may be any sum so expressed shall not be a less than 8-1/3% of his total emoluments and not more than his total emoluments.

- (c) When an employee opt to subscribe at the minimum rate of 6%, or 8-1/3 per cent, as the case may be, the subscription shall be rounded to the nearest whole rupee and for this purpose, 50 paise and more shall be rounded to the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the emoluments of a subscriber shall be—

- (a) in the case of subscriber who was in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date ; provided that—

- (i) if the subscriber was on half day leave on the said date and opted not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
- (ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on half pay leave on the said date and continues to be on leave and has opted to subscribe during such leave, his emoluments to which he would have been entitled had he been on duty or on duty in India as the case may be;

- (b) In the case of a subscriber who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely :—

- (a) if he was on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his pay bill for that month ;
- (b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and opted not to subscribe during such half pay leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;
- (c) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on half pay leave and has opted to subscribe during such leave by the deduction which he makes or cause to be made in this behalf from his salary for the month.
- (d) if he has entered into service for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from the salary bill for that month during which he joins the Fund ;
- (e) if he was on deputation on the 31st March of the preceding year by the amount credited by him in the Fund of the Corporation on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be,—

- (a) reduced once at any time during the course of the year;
- (b) enhanced twice during the course of the year; or
- (c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1).

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has opted not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

11. Transfer on deputation to a post under the Government or any other organisation or deputation of India.—When subscriber is transferred or sent on deputation out of India, he shall remain subject to these rules in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

12. Realisation of subscriptions.—(1) When the emoluments are drawn from the Fund, recovery of subscriptions and the principal and interest of advances, if any, granted from the Fund shall be made direct from the emoluments.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer.

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is on default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 9, the total amount due to the Fund on account of arrears or subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 13, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of rule 14:

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

13. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Corporation shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Central Government in respect of the General Provident Fund for the Central Government Employees:

Provided that if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent, all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent, shall be allowed interest at the rate of 4 per cent:

Provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other Provident Fund of the Central Government and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in his Fund under rule 26 shall also be allowed interest at the rate of 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund under a provision similar to that of the first proviso to this rule.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner:

- (i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less sums, if any, withdrawn during the current year, interest for twelve months;
- (ii) on sums withdrawn during the current year interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal.
- (iii) on all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year interest from the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise and more counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) In this rule, the date of deposit, shall, in the case of recovery from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifty day of that month, but if it is received on or after the fifty day of that month the first day of the next succeeding month:

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn:

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule (2) of rule 12, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month:

Provided also that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under rules 20, 21 or 22 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated or the date of posting the cheque, as the case may be:

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government of an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he inform the Accounts Officer that he does not wish to receive it: but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amount which under sub-rule (3) of rule 12, rule 20, or rule 21 are repaid to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this rule and so far as may be in the manner prescribed in this rule.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump-sum, or in default be ordered to be recovered by deduction one lump-sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made

in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-rule the rate of interest, to be charged on overdrawn amount would be 2-1/2 per cent over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-rule (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Corporation account under a distinct sub-head 'Interest on overdrawals from Provident Fund' under the head '049-Interest Receipts-C—other interest receipts of Corporation—other Receipts'.

14. Advance from the Fund.—(1) The Director General or any other Officer authorised by him in this behalf, may sanction the payment to any subscriber in the prescribed Form as specified in Schedule-II of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely:—

- (a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.
- (b) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him; in the following cases, namely:—
 - (i) for the education outside India in respect of an academic, a technical, a professional or vocational course beyond the high school stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is or not less than three years duration;
- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscribers' status which, by customary usage the subscribers' has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source
- (e) to meet the cost of his defence where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;
- (f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society.

(2) The Director General may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-rule (3) of rule 25.

Note 1.—For the purpose of this rule pay includes dearness pay, where admissible.

Note 2.—A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under clause (b) of sub-rule (1) of rule 14.

15. Recovery of advance.—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so opt and in any case not more than twenty four. In special cases where amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (2) of rule 14, the sanctioning authority may fix such number of instalments exceeding twenty four but not exceeding thirty six. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be fixed in whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary, to admit the fixation of such instalments.

(2) Recovery of advances shall be made in the manner specified in rule 12 for the realisation of subscription, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may on the subscriber's written request, be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of amount withdrawn shall be forthwith repaid by the subscriber to the Fund. Or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the Accounts Officer.

Provided that before such advance is disallowed, the subscriber shall be given reasonable opportunity to explain the sanctioning authority to writing within 15 days of the receipt of the communication that why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days, it shall be referred to the Director General for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in the sub-rule.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited to the subscriber's account in the Fund.

16. Wrongful use of advance.—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within 15 days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of 15 days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note:—The term "emoluments" in this rule shall not include subsistence grant.

17. Withdrawal from the Fund.—(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned to the subscriber in the prescribed Form as specified in Schedule-II, by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (2) of rule 14, at any time, after the completion of twenty years of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit

in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

- (a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely :—
 - (i) for the education outside India for academic, technical, professional or a vocational course beyond the high school stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage;
- (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters and of any other family relation actually dependent on him;
- (c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(2) After the completion of (Ten years) of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, a subscriber will be allowed withdrawals from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :

- (i) building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence including the cost of the site;
- (ii) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence;
- (iii) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
- (iv) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
- (v) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty;
- (vi) constructing a house on a site purchased under clause (iii).
- (vii) within six months before the date of the subscriber's retirement for the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.
- (viii) once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Corporation employees on self financing and contributory basis.

Note 1.—A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (i), (iii), (iv), (vi) or sub-rule (2) for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 18.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under clauses (i), (iii) and

(vi) of sub-rule (2) for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a readybuilt flat at the place of his duty.

Note 2.—Withdrawal under clauses (i), (iv), (v) or (vi) of sub-rule (2) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3.—The amount of withdrawal sanctioned under clause (ii) of sub-rule (2) shall not exceed $\frac{3}{4}$ th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (i) reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is $\frac{3}{4}$ th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 4.—Withdrawal under clause (i) or (iv) of sub rule (2) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or Husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5.—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flats covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clause (i) or (vi) of sub-rule (2) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Note 6.—A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 14 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-rule (3) of rule 25.

18. Conditions for withdrawal:—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes, specified in rule 17 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto $\frac{3}{4}$ th of the balance at his credit in the Fund having regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to this credit in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-rule (2) of rule 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under rule 2(a) and 3(b) of the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house building purposes.

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government sources, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and 3(b) of the aforesaid scheme.

Note 1.—A withdrawal sanctioned to a subscriber under clause (i) of sub-rule (2) of rule 17 may be drawn in instalments, the number which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

Note 2.—In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for rule 16.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from Fund under rule 17 shall satisfy the sanctioning authority with in such reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Director General :

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule the subscriber shall be given a reasonable opportunity to explain in writing and within 15 days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-rule.

.. (3) (a) A subscriber who has been permitted under clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (2) of rule 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house, built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Director General), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Director General :

Provided that such permission shall not be necessary for—

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or
- (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Director General, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity for making a representation in the matter cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note A.—A subscriber who has taken loan from ESI Corporation in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Corporation shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

Declaration

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident

Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Corporation."

19. Conversion of an advance into a withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 14 for any of the purposes specified therein may convert, at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 17 and 18.

Note 1.—The Head of office in case of non-gazetted subscribers and the Treasury Officer concerned in the case of gazetted subscribers may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer that authority shall endorse a copy of the letter forwarding the subscriber's intimation to the Treasury Officer from where he draws his pay in order to permit stoppage of further recoveries.

Note 2.—For the purpose of sub-rule (1) of rule 18, the amount of subscription, with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

20 Final withdrawal of accumulations in the Fund.—When a subscriber quits the service of the Corporation the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service, shall if required to do so by the Director General, repay any amount paid to him from the fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 13 in the manner prescribed in the proviso to rule 21. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation 1.—A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, with or without a break in service shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of provident fund rules) and without retaining any connection with his former post, in such case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred—

- (a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that Fund, if the new post is in another department of the Central Government, or
- (b) to a new account under the State Government concerned if the new post, is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions and interest.

Note.—Transfers shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Central Government. In cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation II.—When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed or is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body to his new Provident Fund Account under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Central Government. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government servant on transfer from one post to another:

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, or a subscriber opting for service under a public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agreed to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund. The amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. Retirement of Subscriber.—When a subscriber—

- (a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department on leave preparatory to retirement combined with vacation, or
- (b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall if require to do so by the Director General, repay the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 13 in cash or securities by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) or rule 14.

22. Procedure on death of subscriber.—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made—

(i) When the subscriber leaves a family—

- (a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members or his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;
- (b) if no such nomination in favour of member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

- (1) sons who have attained majority;
- (2) sons of a deceased son who have attained majority;
- (3) married daughters whose husbands are alive;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;
- (c) If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4);

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) to the first proviso.

- (ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Deposit Linked Insurance Scheme.—On the death of a subscriber on or before 30th September, 1991 and to whom rule 24 does not apply, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that—

- (a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of—
 - (i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,300 or more in the pre-revised scale;
 - (ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1,300 in the pre-revised scale;
 - (iii) Rs. 1,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291 or more but less than Rs. 900 in the pre-revised scale;
 - (iv) Rs. 1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period or three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291 in the pre-revised scale.

- (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000;
- (c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

Note 1.—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above:—

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 13;
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.—Payments under this scheme should be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.

Note 4.—This scheme also applies to those subscribers to the Fund who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department

into such a body and who, on such transfer, opt, in terms of option given to them, to subscribe to this Fund in accordance with these rules.

Note 5. (a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefit of the Fund under rule 26 or 27, but dies before completion of three years service, or as the case may be, five years service from the date of his admission to the fund, that period of his service under the previous employer in respect where of the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purpose of this rule.

(c) This scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note-6. The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

24. Deposit Linked Insurance Revised Scheme.—On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that—

- a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have fallen below the limits of—
 - (i) Rs. 12,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of maximum of the pay scale of which is Rs. 4,000 or more.
 - (ii) Rs. 7,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2,900 or more but less than Rs. 4,000.
 - (iii) Rs. 4,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,151 or more but less than Rs. 2,900;
 - (iv) Rs. 3,000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,151;
- (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 30,000.
- (c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his/her death.

Note-1. The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the maximum balance prescribed above:—

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 13;
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note-2. Payment under this scheme will be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note-3. Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note-4. The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these rules.

Note-5. (a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefits of the fund under rule 26 or 27 but died before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been recovered, shall count for the purpose of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for the purposes of this rule.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note-6. The Budget Estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

25. Manner of payment of amount in the Fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund become payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person whom, under these rules, any amount of policy is to be paid, assigned or reassigned or delivered; is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the lunacy Act, 1912 (4 of 1912) the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic:

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a magistrate to be lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) or section 93 of the lunacy Act, 1912 (4 of 1912), to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit shall be paid for the maintenance of such member of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payment of the amount to be withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely:—

- (i) is enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of office shall send to every subscriber necessary Forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of office or department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made:—

- (a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Account Statement for the year

ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

- (b) for the amount indicated in his ledger account in case of the Accounts Statement has not been received by the subscriber.
- (ii) the Head of Office or Department shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by subscriber after the period covered by the last statement or the subscriber's accounts sent by the Accounts Officer.
- (iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.
- (iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.
- (v) after forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as formal sanction of sanctioning authority is received by him.

Note.—When the amount standing to the credit on a subscriber has become payable under rules 20, 21 and 22 the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-rule (3).

26. Procedure on transfer of a Government servant from one Department to another.—(a) If a Government servant who is a subscriber to any other non-contributory Provident Fund if the Central Government or of a State Government is permanently transferred to pensionable service in a Department of the Central Government in which he is governed by these rules, the amount of subscriptions, together with interest thereon, standing to his credit to such other Fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the Fund:

Provided that where a subscriber was subscribing to a non-contributory Provident Fund of a State Government the consent of that Government shall be obtained.

(b) If a Government servant who is a subscriber to the State Railways Provident Fund or any other contributory Provident Fund of the Central Government or a State Contributory Provident Fund is permanently transferred to pensionable service in a Department of Central Government in which he is governed by these rules and unless such a subscriber elects to continue to be governed by the rules of such Fund, when the rules option is given:—

- (i) the amount of subscriptions with interest thereon, standing to his credit in such Contributory Provident Fund on the date of transfer shall with the consent of the other Government, if any, be transferred to his credit in the Fund;
- (ii) the amount of Government contributions, with interest thereon, standing to his credit in such contributory Provident Fund shall, with the consent of the other Government, if any, be credited to the Central Revenue (Civil);
- (iii) he shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer, the extent permissible under the relevant pension rules.

Note-1.—The provisions of this rule does not apply to a subscriber who has retired from service, or to a subscriber who was holding the former appointment on contract.

Note-2.—The provisions of this rule shall, however apply to persons, who are appointed without break whether temporarily or permanently to a post carrying the benefits of these rules after resignation or retirement from service under another Department of Central Government or under the State Government.

27. Procedure on transfer.—On transfer to Government service of a person from the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860. If a Government servant admitted to the benefit of the Fund was subscriber to any Provident Fund of a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with the interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of that body.

28. Transfer of amount to the Contributory Provident Fund (India).—If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund (India) the amount of his subscriptions, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his account in the Contributory Provident Fund (India).

Note.—The provision of this rule do not apply to a subscriber who is appointed on contract or who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service in another post carrying contributory Provident Fund benefits.

29. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases.—When the Standing Committee is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, it may, notwithstanding anything contained in these rules after recording its reasons for so doing deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

30. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription.—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

31. Annual statement of account to be supplied to subscriber.—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber's statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under rule 7; or under the corresponding rule heretofore in force.

(b) has acquired a family, in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-rule (1) or rule 7.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness to the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the Statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

32. Interpretation.—If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government in the Ministry of Labour shall decide the same.

INSTRUCTIONS FOR THE SUBSCRIBER.--

- (a) Your name may be filed in:
 (b) Name of the Fund may be completed suitably.
 (c) Definition of term "family" as given in the General Provident Funds (CS) Rules, 1960 is reproduced below:

Family means:—

- (i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparents :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts officer that she shall continue to be so regarded.

- (ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancelled such notice in writing.

Note.—Child means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

- (d) Col. 4 If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.
 (e) Col. 5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.
 (f) Col. 6 Do not mention your name.
 (g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

SCHEDULE—II

[See rules 14(3) and 17(1)]

APPLICATION FOR ADVANCE/WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND

1. Name of the subscriber _____
 2. Account Number _____
 3. Designation _____
 4. (1) Pay Rs _____
 (2) Monthly subscription Rs. _____
 5. In case of withdrawal
 - (i) Date of Birth _____
 - (ii) Date of appointment _____
 - (iii) Date of superannuation _____
- Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:—
- (i) Closing balance as per statement for the year 19 _____ Rs. _____
 - (ii) Credit from _____ to _____ on account of monthly subscription Rs. _____
 - (iii) Refunds Rs. _____
 - (iv) Withdrawals during the period from _____ to _____ Rs. _____
 - (v) Net balance at credit Rs. _____

6. Amount of advance outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them.
 Amount of advance taken Rs. _____
 Balance outstanding as on date Rs. _____
7. Amount of advance required Rs. _____
8. (a) Purpose for which the advance is required _____
 (b) Rules under which the request is covered _____
 (c) If advance is sought for House Building etc. following information may be given :—
 (1) Location and measurement of the plot _____
 (2) Whether plot is freehold or on lease _____
 (3) Plan for construction _____
 (4) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society, the location and measurements, etc. _____
 (5) Cost of construction _____
 (6) If the purchase of flat is from DDA or any Housing Board etc. the location, dimension, etc. may be given _____
 (d) If advance is required for education of children, following details may be given :—
 (1) Name of the son/daughter _____
 (2) Class and Institution/College where studying _____
 (3) Whether a day-scholar or a hostler _____
 (e) If advance is required for treatment of ailing family members, following details may be given :—
 (1) Name of the patient and relationship _____
 (2) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment _____
 (3) Whether outdoor/indoor patient _____
 (4) Whether reimbursement available or not _____
- Note:—In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate or documentary evidence would be required.
9. Amount of the consolidated advance (items 6 and 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid Rs. _____
 in instalments.
10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance.

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Signature of Applicant

Name _____

Designation _____

Section/Branch _____

Dated:—

Recommendation/Remarks of
the Competent Authority

Dated _____

Signature _____

Designation _____

[File No. S-65012/1/90-SS. II]
J.P. SHUKLA Under Secy.